राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारीत

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार, 06 अप्रैल 2022 वर्ष-4, अंक-70 पृष्ठ-08 मूल्य-01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

पीएम मोदी से मिला जम्मू-कश्मीर के उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल

जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में कश्मीर हाटेलियर्स क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक चाया, कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड डस्ट्रीज के अध्यक्ष शेख आशिक के अलावा बलदेव सिंह रैना, शौकत चौधरी और समीर अहमद शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ.दरक्षां अंद्राबी ने किया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल शेख आशिक ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति सहित अन्य विभिन्न मुद्दों को विवरण ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया। उन्होंने नियमित तौर पर जेद्दा और दुबई के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की मांग की ताकि इससे प्रदेश के उद्योगपति अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सकें। यह तभी संभव होगा जब उक्त देशों के लिए जम्मू-कश्मीर से सीधी हवाई सेवा नियमित तौर पर होगी। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और व्यवसायिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। काफी हद तक रोजगार के भी कई साधन पैदा होगा। जम्मू-कश्मीर में रोशनी एक्ट सहित गुलमर्ग और पहलगाम में लीज पर भूमि देने सहित अन्य मुद्दों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। कश्मीर के कालीन उद्योग की जीआई टैगिंग सहित इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के विभिन्न पहलूओं पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को ध्यान से सुना और कहा कि उनकी उचित मांगों पर पूरा गौर किया जाएगा।

बालासाहेब का चेला हूं, गोली मार दो पर झुकूगा नहीं, ईडी के एक्शन पर भड़के राउत

मुंबई । शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी की ओर से अपना फ्लैट और प्लॉट कुर्क करने को लेकर कहा कि भले मुझे ही गोली मार दी जाए या फिर जेल भेज दिया जाए, मैं चुप नहीं बैठूंगा। राउत ने कहा कि मैं बालासाहेब ठाकरे का चेला हूं और झुक नहीं सकता। राउत ने कहा, प्रॉपर्टी का मतलब आखिर क्या होता है। क्या मैं मेहुल चोकसी हूं, नीरव मोदी हूं या फिर विजय माल्या हूं। मैं अंबानी या अडानी भी नहीं हूं। मैं जिस घर में रहता हूं, वह छोटा सा है। मेरा जो पैतृक स्थान अलीबाग है, वहां एक एकड़ जमीन भी नहीं है। जो भी हमने लिया है, वह मेहनत की कमाई से खरीद है, जो 2009 में ली गई थी। राउत ने ईडी की कार्रवाई को बदले का एक्शन बताया। उन्होंने कहा, यह जो कुछ भी हो रहा है, वह बदले की कार्रवाई से हो रहा है। मुझे पहले ही धमकियां मिल रही थीं कि यदि आप महाराष्ट्र की सरकार गिराने में सहयोग नहीं करते हैं, तब फिर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होगी। बेहद तल्ख अंदाज में दिख रहे शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे हमें गोली मार दो। प्रॉपर्टी जब्त कर लो या फिर जेल भेज दो। राउत बालासाहेब ठाकरे का चेला है, चुप नहीं बैठेगा और आप लोगों की पोल खोलता रहेगा। दो सालों से कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठा। अब जिसे फुदकना है, फुदकता रहे, नाचता रहे। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है।

मोदी ने बीजेपी सांसदों को दिया कड़ा संदेश, सेवा भाव से जनता के बीच करें काम

नेशनल डेस्क ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थापना दिवस से एक दिन पहले मंगलवार को पार्टी के सांसदों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वह सेवा व समर्पण भाव के साथ जनता के बीच जाकर काम करें और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। प्रधानमंत्री ने आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में यह बात कही। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से स्थापना दिवस और सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रतिदिन एक बड़ा आयोजन करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को कहा। ज्ञात हो कि भाजपा अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 दिनों तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। पार्टी ने इस दौरान कई कार्यक्रमों के आयोजन का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के स्थापना दिवस पर बुधवार को डिजिटल माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। संसदीय दल की बैठक में पूर्वोत्तर में भाजपा के उदय का भी उल्लेख किया गया। पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में या तो भाजपा या फिर उसके नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकारें हैं। नगालैंड से भाजपा की पहली महिला सांसद एस फान्गनॉन कोन्यक भी आज संसदीय दल की बैठक में शामिल हुईं। वह राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई हैं। सूत्रों ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बैठक में राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंचने का उल्लेख किया और इसे पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताया। बैठक के बाद संवाददाताओं को सबोधित करते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से पार्टी की ओर से आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। जोशी के मुताबिक मोदी ने कहा, ''उन्हें (सांसदों को) जनसेवा के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। पार्टी के सांसद और अन्य सदस्य सात अप्रैल को ''आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्रों के प्रभावों को रेखांकित करेंगे। आठ और नौ अप्रैल को होने वाले कार्यक्रमों के केंद्र में गरीबों के लिए आवास योजना और हर घर नल से जल योजना रहेगी। पार्टी नौ अप्रैल को ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती भी व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। जोशी ने कहा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने की केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट

नई दिल्ली । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किये जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत और ऊधमसिंहनगर के खटीमा) के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत व बचाव कार्यों के लिये पुलिस, आईटीबीपी व एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल/हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दल में सम्मिलित व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय प्रस्तावित है। इस पर लगभग 05 करोड़ 45 लाख रूपए का व्यय भार अनुमानित है। इसमें केंद्र का सहयोग निवेदित है। मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिये राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किये जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिये निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिये केंद्र से 25 करोड़ रूपए का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत किये जाने का भी अनुरोध किया।

धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर मांगा 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज

नई दिल्ली ।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मंगलवार को भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड को कश्मीर तर्ज पर 2000 करोड़ रुपए का बागवानी पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में बागवानी की अपार सम्भावनाएं हैं। धामी ने प्रधानमंत्री से राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखकर जीएसटी प्रतिकर अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखंड में नवीनतम तकनीक व वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना और फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) की स्थापना का आग्रह किया। टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड की अंशधारिता में उत्तर प्रदेश के अंश का उत्तराखण्ड को हस्तांतरित करने के लिए न्यायालय से बाहर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र सरकार की विशेष पहल का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल के पौराणिक स्थलों व मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिए मानसखण्ड मंदिर माला मिशन की स्वीकृति देने और पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के उपरांत डी.पी.आर तैयार कर ली गई है। उन्होंने ऋषिकेश-डोईवाला रेलवे ट्रेक के निर्माण और देहरादून रेलवे स्टेशन को हरावाला स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, योग व आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रसिद्ध है। यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से आयुष पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलिंगकांग के मध्य 05 किमी टनल और वेदांग से गौ व सिपु तक 20 किमी सड़क मार्ग का निर्माण किए जाने तवाघाट से बेदांग तक का मार्ग कनेक्ट हो जाएगा। यह जौलींगकांग एवं बेदांग की दूरी 161 किमी कम कर देगा। इसी प्रकार सिपु से तोला के मध्य लगभग 22 किमी लंबाई की टनल के निर्माण से दारमा वैली और जोहर वैली एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। मिलम से लष्थल तक 30 किमी टनल के निर्माण से जनपद पिथौरागढ़ की जोहार घाट व जनपद चमोली का लष्थल सड़क मार्ग से जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उक्त तीनों टनलों के निर्माण को स्वीकृति दिये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पार्लियामेंट हाउस में भेंट की। मुख्यमंत्री सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू करने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया।

केंद्र का किसानों को आश्वासन- दुनिया में कीमतें बढ़ने के बाद भी मौजूदा मूल्य पर ही मिलेंगे उर्वरक

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को देश के किसानों को आश्वत किया कि आगामी रबी और खरीफ मौसम में उन्हें मौजूदा कीमत पर ही पर्याप्त उर्वरकों की आपूर्ति की जाएगी। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पिछले साल भी उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर बड़ी चिंता थी और नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने समय-समय पर निर्णय लेते हुए किसानों की जरूरतों को 'समय पर और सही दाम पर' पूरा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि उर्वरकों की जो कीमत आज है, वही कीमत बनी रहेगी, हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों में चार-पांच गुना तक वृद्धि हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद सरकार किसानों को सब्सिडी देती रहेगी और उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास रहा है कि उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़े और इस क्रम में राष्ट्रीय यूरिया नीति भी तैयार की गयी है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के गैस आधारित 25 संयंत्र शुरू किए गए हैं ।

33 हजार किलोमीटर बाइक चलाकर 9 टन वजनी शिवलिंग को लेकर धौलपुर पहुंचीं बुलेट रानी

धौलपुर । 21 राज्यों में 33 हजार किलोमीटर बाइक चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने वाली बुलेट रानी राजलक्ष्मी मंदा एक ट्रक में 9 टन वजनी शिवलिंग को लेकर धौलपुर पहुंचीं। दरअसल, बुलेट रानी राजलक्ष्मी ने बताया कि धर्म की रक्षा करने के लिए उनकी 25 सदस्य टीम ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर एक संकल्प लिया था। संकल्प के तहत उन्होंने एक ट्रक में 9 फीट ऊंची और 9 टन वजनी शिवलिंग की प्रतिमा के साथ भगवान शिव के परिवार को रखकर उन्हें सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के बाद भदौही उत्तर प्रदेश में स्थापित करने बीड़ा उठाया। बुलेट रानी ने बताया कि धर्म की रक्षा करने का संदेश देकर उनकी टीम फलाहरी बाबा के नेतृत्व में लीगल राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 9500 किलोमीटर का सफर कर रही है। ट्रक में शिव परिवार को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद सुंदरवन भदौही में उनकी प्रतिष्ठा कराई जानी है। शिव परिवार को ट्रक में लेकर खुद ट्रक चलाकर वहां अब तक 9 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं।

एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी बंद किया

मोदी सरकार ने 22 यूट्यूब चैनल्स, तीन टविटर अकाउंट पर की डिजिटल स्ट्राइक

नई दिल्ली।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी रुल 2021 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए 22 यूट्यूब चैनल्स, तीन टविटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल्स के पास कुल 260 करोड़ व्यूअरशिप थी। इन अकाउंट्स और चैनल्स का इस्तेमाल संवेदनशील और भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामलों में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलान के लिए किया जा रहा था। आईटी नियम 2021 के आधार पर यह पहला मौका है, जब भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर एक्शन लिया गया है। बता दें कि सरकार पिछले साल फरवरी में आईटी रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया था। लेटेस्ट ब्लॉकिंग ऑर्डर के तहत 18 भारतीय और 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। इन यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल विभिन्न मुद्दों पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था। खासकर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर फर्जी पोस्ट इन चैनल्स के जरिए किए जा रहे थे। विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पोस्ट किए गए भारत विरोधी कंटेंट को भी ब्लॉक किया गया है। जांच में पाया गया है कि भारतीय यूट्यूब चैनल्स द्वारा यूक्रेन की स्थिति पर भी कई गलत जानकारियां शेयर की गई हैं। दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की मंशा से इन चैनल्स द्वारा पोस्ट किया जा रहा था। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल्स में कई टीवी चैनल्स के लोगो और टैम्पलेट का इस्तेमाल किया गया था। इन चैनल्स ने अपने पोस्ट के थम्ब नेल में कई टीवी एंकर्स की तस्वीर भी यूज की है, जिससे व्युअर्स को गुमराह किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत थम्बनेल और टाइटल के साथ पोस्ट किए गए थे। कुछ मामलों में भारत के खिलाफ फेक न्यूज को पाकिस्तान से फैलाया जा रहा था इस फैसले के साथ पिछले साल दिसंबर यानी दिसंबर 2021 से अब तक मंत्रालय ने 78 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है। अब तक मंत्रालय ने 78 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है। इसके साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन किया गया है, जो देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के मुद्दों को गलत जानकारी फैला रहे थे।मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया एनवॉरमेंट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करती है।

खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, जिन्ना वाली सोच

नई दिल्ली ।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बयान को लेकर देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है। रहमानी के बयान पर प्रतिक्रिया देकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे जिन्ना की सोच से प्रेरित बताया , वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बागपत से लोकसभा सांसद सत्यपाल सिंह ने दावा किया कि भाजपा सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिल रहा है। जबकि दिल्ली से भाजपा लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा ने बयान देने वाले वाले को पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली। केंद्रीय मंत्री सिंह ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देकर कहा कि शायद दुनिया मे भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां हालात खराब होने की बात कहने के बावजूद लोग प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब इनके लिए हालात खराब है,तब ये मठ मंदिरों में घुसकर मारने की तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये वहीं लोग कह रहे हैं जिनके दिमाग मे जिन्ना का जिन्न बैठ गया है। वहीं सांसद सत्यपाल सिंह ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान को गलत, दुर्भाग्यपूर्ण और बहकाने वाला बयान बताकर तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों को जितना अधिकार मिला हुआ है उतना बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को भी नहीं है। सिंह ने भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिलने का दावा करते हुए ।

नकवी बोले- हज यात्रा को लेकर हमने कर ली पूरी तैयारी, बस सउदी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा

नई दिल्ली । केंद्र की मोदी कैबिनेट के सदस्य केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि इस साल हज की यात्रा के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और वह इस संबंध में सउदी अरब की सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान एक सदस्य की ओर से दो साल से हज की यात्रा ना होने का मुद्दा उठाए जाने के जवाब में नकवी ने यह बात कही। नकवी ने कहा, 'कोरोना महामारी के दौरान पिछले दो वर्ष से भारतीय हज यात्रा पर नहीं जा सके हैं। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी तैयारियां हैं।' उन्होंने कहा कि हज यात्रा सऊदी अरब में होती है और इस बारे में निर्णय लेने का काम वहां की सरकार का है। उन्होंने कहा, 'सऊदी सरकार को तय करना है कि हज यात्रा कब होगी और कितने लोग हिंदुस्तान से जाएंगे। सऊदी अरब की सरकार जैसे ही यह तय करेगी, हम उसके साथ हैं। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।' नकवी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद रिकॉर्ड दो लाख से ज्यादा हज यात्री हिंदुस्तान से हज यात्रा करने गए हैं। इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पिछले दो साल से कोविड-19 की वजह से हज यात्रा नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने यात्रा के लिए फॉर्म भर कर जमा कर दिया है लेकिन मगर अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हज कमेटी में 11 सदस्यों को नामित किया गया है और इसमें कुछ खामियां रह गई है।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सुविचार बीते हुए कल से सीखे, आज के लिए जिए और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखे। - अल्बर्ट आइस्टीन

संपादकीय

चीन में बढ़ा संक्रमण

अभी कोरोना पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। दुनिया के ज्यादातर इलाकों में संक्रमण में कमी आई है, पर संपूर्ण राहत से हम अभी काफी दूर हैं। विडंबना देखिए, जब भारत में कुल 12,575 सक्रिय मामले हैं, तब चीन में प्रतिदिन 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चीन में संक्रमण न जाने किस ऊंचाई पर पहुंचने को बेताब है, मगर तारीफ करनी होगी कि उसने पूरी कड़ाई से इसके फैलाव को बहुत हद तक रोक रखा है। चीन में जो फैला है, वह एक नए प्रकार का ओमीक्रोन है, जबकि ऐसा लगता है कि भारत संक्रमण के शिकंजे से निकल आया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को दैनिक नए संक्रमणों की संख्या 715 दिनों के बाद 1,000 अंक से नीचे आई है। साथ ही, 714 दिनों के अंतराल के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 13,000 अंक से नीचे आई है। भारत में बीमारी से उबरने वालों की संख्या 4,24,95,089 से ज्यादा हो गई है। चीन जैसी अत्यधिक कड़ाई न करने के बावजूद दो साल बाद भारत राहत की सांस ले रहा है। मौजूदा संक्रमण की लहर और लगे कड़े प्रतिबंधों के बीच चीनी नागरिकों के धैर्य की परीक्षा हो रही है। ध्यान रहे, यह ऐसा समय है, जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा फिर से खुल गया है, पर चीन के अनेक शहरों में आंशिक या संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है। चीन लॉकडाउन में ढील देकर पश्चिमी देशों की तरह कोताही नहीं करना चाहता है। वहां काम भी बाधित हुआ है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, यह अच्छी बात है कि मौतों की संख्या नियंत्रित है। चीन के लगभग 70 प्रतिशत मामले अकेले शंघाई शहर में हैं, लगभग ढाई करोड़ लोगों की आनन-फानन में जांच की गई है। चीनी सरकार की कोशिश है कि संक्रमण पर जल्द से जल्द काबू किया जाए। अकेले शंघाई में 8,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, चीन रोकथाम के लिए अपने नागरिकों की युद्ध स्तर पर कोरोना जांच कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार, शंघाई में ही ढाई करोड़ से ज्यादा लोग क्वारंटीन हैं। सान्या शहर में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सभी परिवहन माध्यमों को निलंबित कर दिया गया है। शुरू में सिर्फ चार दिनों तक लॉकडाउन चलने की योजना थी, लेकिन इसका समय निरंतर बढ़ रहा है। ताजा भोजन की कमी होने लगी है। चीनी अधिकारी इसलिए भी सख्ती बरत रहे हैं, क्योंकि चीन ने लंबे समय तक शून्य कोविड रणनीति का सफल प्रयोग किया था। किसी समय चीन दुनिया के पीड़ित देशों को नसीहत देता था। कुछ देशों में संक्रमण का चीन ने मखौल भी बनाया था। सुरक्षित व स्वस्थ चीन के कई वीडियो दुनिया भर में प्रसारित-प्रचारित किए गए थे। चीन को आदर्श माना जाता था कि उसने अपने यहां कोविड को फैलने नहीं दिया, पर ताजा संक्रमणों ने चीन के दामन पर दाग लगा दिए हैं। हम कैसे भूल जाएं, चीन ही वह देश है, जहां 2019 के अंत में वुहान में पहली बार कोरोना वायरस का पता चला था। हालांकि, दुनिया जान नहीं पाई है कि कोरोना कैसे, कहां पनपा, क्योंकि चीन ने एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास दिलाया। गत मार्च तक उसने स्थानीय लॉकडाउन, सामूहिक परीक्षण और यात्रा प्रतिबंधों के साथ दैनिक मामलों को सफलतापूर्वक तिहरे अंकों तक नीचे रखा था। लेकिन संक्रमण के चलते जब शंघाई की सड़कें सूनी पड़ी हैं, तब भारत को सावधान रहते चीन के अनुभव से भी सीखना चाहिए।

संकल्प-सिद्धि की पर्याय बनी भाजपा

(लेखक -विष्णुदत्त शर्मा)/ (6 अप्रैल स्थापना दिवस पर विशेष)

स्वाधीनता के बाद 1951 में देश की दलीय राजनीति में राष्ट्रवादियों द्वारा एक 'दीया' जलाया गया था ताकि लोकतंत्र का उजाला राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। विदेशी दासता से मुक्ति के बाद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य यही था। उसका चुनाव चिन्ह 'दीपक' था। यह अलग बात है कि उस दौर में स्वतंत्र भारत में कॉग्रेस की स्वीकार्यता व्यापक थी और किसी भी नयी राजनीतिक विचारधारा के लिए राह कठिन थी। यही वजह है कि एक नई पार्टी के तौर पर अखिल भारतीय जनसंघ को 1952 के आम संसदीय चुनाव में 2 सीटें ही मिलीं। अनेक राजनीतिक कारणों से जनता पार्टी में विलय, फिर जनसंघ की पहचान के साथ अंततः 6 अप्रैल 1980 को 'भारतीय जनता पार्टी' ने साकार रूप लिया। प्रारंभिक चार साल के संघर्ष के बाद 1984 के आम चुनाव में उसे भी मात्र 2 सीटें मिलीं। जनसंघ और भाजपा दोनों में यह एक अद्भुत समानता देखी जा सकती है कि पर्याप्त पहचान बना लेने के बावजूद दोनों का खाता 2 से ही खुला। स्मरण रहे कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गाँधी जी और सरदार पटेल के आग्रह पर स्वतंत्रता के बाद बनी पहली सरकार में मंत्री बनाया गया था। परन्तु वे सरकार में रहते हुए लोककल्याण और राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके बाद पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि के नेतृत्व में भी भाजपा लंबे समय तक विपक्ष में ही रही, परन्तु उसने कभी अपने संकल्पों के साथ समझौता नहीं किया। भाजपा ने तीन दशक से अधिक समय तक भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। विपक्षी दल होते हुए भी भाजपा और उसके नेतृत्व ने भारत ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया में अपनी अनुकरणीय छाप छोड़ी।

निःसंदेह जनसंघ के बाद भाजपा तक की यात्रा में दल का नाम भले ही बदला, लेकिन न तो उसके मुद्दे बदले और न ही उसकी नीयत और निष्ठा बदली। 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी भी हिन्दुत्व के लिए प्रतिबद्धता के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में धारा 370 हटाने, अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण तथा सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता संहिता के प्रति पहले दिन से ही संकल्पित रही। इसलिए 2 सीटों पर विजय से शुरू हुआ संसदीय सफर तीन दशक बाद 300 के पार भी पहुंच गया। आज देश के हर कोने में भाजपा की सशक्त उपस्थिति है। आज भाजपा के बिना कोई राजनीतिक प्रक्रिया सम्भव नहीं है। पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में भाजपा का सत्ता में आना मृग मरीचिका माना जाता था, वहाँ के लोगों ने भी उसे अपना समर्थन दिया और असम, त्रिपुरा, मणिपुर सहित अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकारें बनी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की छोटी से बड़ी पंचायत में भाजपा की प्रभावी उपस्थिति दिनोंदिन बढ़ी है। अब चहुँओर कमल खिलने लगा है। चप्पा चप्पा भाजपा, यह अब नारा नहीं आज की तारीख में एक हकीकत है। इसके साथ ही वे सपने भी हकीकत में बन गए हैं, जो 2 सीटें मिलने के पहले ही देखे गए थे। जिन सपनों को लेकर जनसंघ से लेकर भाजपा तक के कार्यकर्ता गाँव-गाँव गए, वे आज साकार हुए हैं। इस दीर्घकालिक प्रक्रिया में पार्टी ने एक से बढ़कर एक पराक्रमी और परिश्रमी नेतृत्व देखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर नरेन्द्र मोदी तक भाजपा ने देश की दलगत राजनीति में प्रेरणा के पुँज दिए हैं, जिनकी आभा से राजनीतिक जीवन जगमगा रहा है।

ऐसे विलक्षण नेताओं के नेतृत्व में भाजपा कभी भी केवल सत्ता में रहने वाली पार्टी नहीं बनी। उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अपनी प्रतिबद्धता के आलोक में राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को जीया है। जिसके कारण कभी अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाली भाजपा के प्रति जनता का भरोसा बढ़ता गया और कॉग्रेस जैसे वंशवादी दलों का अस्तित्व संकट में आ गया। वंशबेल की राजनीति को देश से समाप्त करने की दिशा में भी भाजपा ने अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है और समय-समय पर साधारण कार्यकर्ताओं के भीतर से ही नेतृत्व दिया है। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हों या अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, एकमात्र भाजपा ने ही परिवारवाद का अंत करते हुए लोकतंत्र में अनूठे मानक तय किये हैं। अपनी 42 वर्ष की यात्रा में आज भाजपा की कोई भी समीक्षा करे तो यह आसानी से समझ सकता है कि पार्टी ने हर दौर में युवा पीढ़ी को अवसर प्रदान कर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक सशक्त नेतृत्व खड़ा किया है।

किसी भी राजनीतिक दल के स्थापना दिवस का स्मरण सच्चे मायने में उसके संकल्पों की समीक्षा और पुनर्व्याख्या का सुअवसर भी है। चार दशक बाद भी यदि किसी राजनीतिक दल की अपनी विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है तो निःसंदेह वह अपनी सही दिशा में चल रहा है। वह अपने संकल्प मार्ग पर निष्कण्टक चल रहा है। इस दृष्टि से विचार करें तो आज पूरी दुनिया देख रही है कि भाजपा ने हर हाल में कश्मीर से धारा 370 को हटाया और श्रीराम मंदिर निर्माण का सपना पूरा किया है। नागरिक संशोधन कानून हो, राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय गौरव का विषय हो, भाजपा की सरकार ने निर्भीकता से कड़े कदम उठाकर विश्व को चकित किया है। विगत सात सालों में मोदी सरकार की योजनाओं ने देश में गरीबों का जीवन बदल दिया है। जन-धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर भाजपा सरकार अब 'अंत्योदय' के विचार का पर्याय बन चुकी है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि एक राजनीतिक दल और उसका नेतृत्व किस प्रकार अपने उन संकल्पों को पूरा करने में सफल सिद्ध हुआ है, जिन्हें पूरा करना असंभव सा लगता था। अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ विश्व में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे भारत ने अपने पुराने स्वाभिमान को भी वापस हासिल किया है। राष्ट्रीय संकट में जनकल्याण की कसौटी पर भी भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाजपा के नेतृत्व में एक अनूठा उदाहरण विश्व के समक्ष रखा है। कोरोना संकट में दुनिया के अनेक देशों ने जहाँ अपने नागरिकों को अपने हाल पर छोड़ दिया, वहीं भारत में भाजपा की मोदी सरकार ने अपने हर नागरिक के जीवन को अमूल्य मानते हुए उनके लिए अनाज के साथ अन्य वस्तुओं को उपलब्ध कराया। स्वदेशी वैक्सीन के आविष्कार में प्रेरक भूमिका तो निभाई ही, हर नागरिक के लिए उसे मुफ्त उपलब्ध कराने हेतु विश्व का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन ड्राइव चला कर दुनिया से अपने सामर्थ्य का लोहा भी मनवा लिया है। ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' ही भाजपा का जीवन-मंत्र है। राष्ट्र-जीवन में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता और उसके प्रति निष्ठा ने ही भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने गौरव दिया है। आमजन के जीवन में बदलाव लाकर उसे देश की मुख्य भूमिका में लाने में भाजपा के नेतृत्व ने अद्भुत सफलता पायी है, यह तथ्य संसार के लगभग सभी राजनीतिक जानकर स्वीकारते हैं। अपने 43 वें वर्ष में प्रवेश कर रहे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने चार दशक पूर्व जो सपने देखे, वह तो साकार हुए ही हैं, साथ ही स्वाधीनता के अमृत वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 के लिए अपना दिशा-सूत्र बना चुका है, जिसको पूरा करने का दारोमदार भी भारतीय जनता पार्टी के कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। निश्चित ही भाजपा अपनी संकल्प शक्ति, निष्ठा और नियति से इसे पूरा करेगी तथा देश के भविष्य-निर्माण की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभा कर संकल्प-सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी।

(लेखक, मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य हैं।)

मोदी के प्रभाव से आगे बढ़ती भाजपा

(लेखक- रमेश सर्राफ धमोरा)

हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव से ही आगे बढ़ रही है। चुनावी नतीजों से पता चलता है कि भाजपा में आज भी किसी भी क्षेत्रीय नेता का कद इतना बड़ा नहीं है कि वह अपने बूते पार्टी को जीता कर भाजपा की सरकार बनवा सके। उत्तर प्रदेश में कई दशकों बाद लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर बहुत से लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चमत्कार बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के प्रभाव के चलते ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 39 वर्षों बाद किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बन पाई है। मगर ऐसा सोचने वाले लोग सही तरीके से राजनीति का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर जैसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पूर्व पंजाब को छोड़कर चारों प्रांतों में भाजपा की सरकार थी। लगातार पांच साल सत्ता में रहने के कारण भाजपा को सत्ता विरोधी लहर से नुकसान होने के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में सभी प्रदेशों में फिर से एक बार सरकार बनाना भाजपा के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। उत्तर प्रदेश को लेकर तो सभी राजनीतिक समीक्षको का मानना था कि इस चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से दूर रहेगी। अधिकांश विश्लेषकों व पत्रकारों का भी मानना था कि वहां पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा होता दिख भी रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ब्राह्मण समाज में खासी नाराजगी व्याप्त हो रही थी। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाता भी भाजपा से बहुत नाराज हो रहे थे। किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश होने के कारण नरेश टिकैत जैसे किसान नेता जाटों को लगातार भाजपा के खिलाफ भड़का रहे थे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी संवैधानिक पद पर होने के उपरान्त भी लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहे थे। जिससे भाजपा बचाव की मुद्रा में थी। विरोधी दलों के नेताओं द्वारा योगी पर जातिवाद करने का आरोप लगाने के कारण योगी की छवि भी खराब हो रही थी। यदि उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में भाजपा की हार हो जाती तो उसका असर आगे कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव व 2024 के लोकसभा चुनाव में भी निश्चय ही पड़ता। परिस्थितियों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता विरोधी लहर को समाप्त करने के लिए खुद मैदान में उतरे और पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से सक्रिय हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सभी चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की वही अमित शाह ग्राउंड लेवल पर पार्टी को एकजुट करने में लग गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांव में तो मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर वोट मांगकर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी वह गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत रंग लाने लगी व पार्टी से नाराज मतदाता धीरे-धीरे फिर से भाजपा खेमे में नजर आने लगे थे। चुनावी नतीजे आने पर भाजपा एक बार फिर अपने चारों प्रदेशों में सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। मगर भाजपा वहां फिर से बहुमत में आ गई। पूर्वोत्तर के मणिपुर जैसे प्रदेश में भी पहली बार भाजपा ने 32 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बना ली। गोवा में भी पार्टी ने पहली बार सबसे अधिक 20 सीटें जीती और आराम से अपनी सरकार बना ली। भाजपा ने चारों ही प्रदेशों में अपने मुख्यमंत्रियों को बरकरार रखा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के खटीमा से चुनाव हार जाने के बाद भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि पार्टी का मानना था कि कम समय में ही मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी की गुटबाजी को दूर कर पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ा था। जिसके फलस्वरूप लगातार दूसरी बार भाजपा उत्तराखंड में सरकार बनाने में सफल रही। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा चेहरों को आगे बढ़ाना चाहतें हैं। उत्तर प्रदेश में भी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हार जाने के बावजूद दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि मौर्य अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। मणिपुर में भाजपा को पहली बार पूरा बहुमत दिलाने पर मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को इनाम स्वरूप दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं गोवा में भी युवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को ही दूसरी बार बार कमान सौंपी गई। हालांकि अपनी विधानसभा सीट पर प्रमोद सावंत महज 666 वोटो से ही चुनाव जीत पाए थे। मगर उन्होंने चुनाव के दौरान पूरी मेहनत की थी। जिसका फल उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बना कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में भाजपा की सरकार चला रहे हैं। सदस्यता के मामले में भी भाजपा देश की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी बन चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाजपा में आज भी प्रादेशिक क्षत्रपों की कमी है। आज भी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द परिक्रमा करती नजर आ रही है। कोई भी चुनाव हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी 2014 के लोकसभा चुनाव में की थी। मोदी व शाह के अलावा भाजपा में ऐसे प्रभावशाली नेताओं की कमी है जो जनता में लोकप्रिय हों। कहने को तो भाजपा में बहुत से केंद्रीय मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री व संगठन से जुड़े बड़े नेता हैं। मगर शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इस बात का दावा कर सके कि वह अपने बूते चुनाव जिता सकता है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले प्रादेशिक नेताओं को धरातल पर काम करना चाहिए ताकि जनता में उनकी पैठ बने। जिससे वो मतदाताओं को आकर्षित कर सकें। भाजपा में आज भी बहुत से हवाई नेता बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी ग्लैमर हावी हो चुका है। कभी जमीन पर सो कर संगठन में काम करने वाले बहुत से नेता आज प्रभावशाली होते ही बड़ी-बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमने लगे हैं। आम कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव कम होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा राजनीति में ईमानदारी की बात करते हैं और स्वयं भी अपने जीवन में पूरी तरह ईमानदारी रखते हैं।

आज के कार्टुन

तत्व ज्ञान

रीराम शर्मा आचार्य

एक बार की बात है कि एक पुण्य व्यक्ति परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला..कई कोस बाद परिवार को प्यास लगने लगी, ज्येष्ठ का महीना था, आसपास पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधू तप करता नजर आया.. व्यक्ति ने साधू से जाकर समस्या बताई..साधू बोले कि यहां से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में छोटी दरिया बहती है। उसने साधू को धन्यवाद बोला..पत्नी एवं बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण वहीं रु कने के लिया बोला और खुद पानी लेने चला गया..जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में पांच व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे..पुण्य आत्मा ने सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया..जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो पांच अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे..पुण्य आत्मा ने फिर सारा पानी उनको पिला दिया..। यही घटना बार-बार हो रही थी..और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधू उसकी तरफ चल पड़ा..बार-बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधू बोला-'हे पुण्य आत्मा तुम बार-बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए.. खाली कर देते हो..इससे तुम्हें क्या लाभ मिला..?' पुण्य आत्मा ने बोला, 'मुझे क्या मिला? या क्या नहीं मिला, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा..पर स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया..।' साधू बोला-'ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित न बचें? अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया..'। पुण्य आत्मा ने पूछा-'कैसे महाराज?' साधू बोला-'मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया..तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था..ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी..फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं..'। इतना कहकर साधू अंतर्ध्यान हो गया..। पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने की बजाय, दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि बताएं..। मित्रो-ये तत्व ज्ञान है..अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है, तो उसे उस परमात्मा से जोड़ दो ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिले!!

सू-दोकू नवताल -2086

3	9				1			
5	4			6	8		1	3
		1		7		9	5	
	8	9		5	3		4	7
6	1		4	9		2	3	
	3	4		1		8		
7	5		8	3			2	4
			6				7	9

सू-दोकू - 2085 का हल

9	6	2	3	4	1	7	5	8
1	4	8	9	7	5	6	2	3
5	7	3	2	6	8	1	4	9
3	2	1	6	9	4	8	7	5
4	8	7	5	1	2	9	3	6
6	9	5	8	3	7	4	1	2
8	3	4	7	2	6	5	9	1
2	1	6	4	5	9	3	8	7
7	5	9	1	8	3	2	6	4

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3 X 3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

फिल्म वर्ग पहेली- 2086

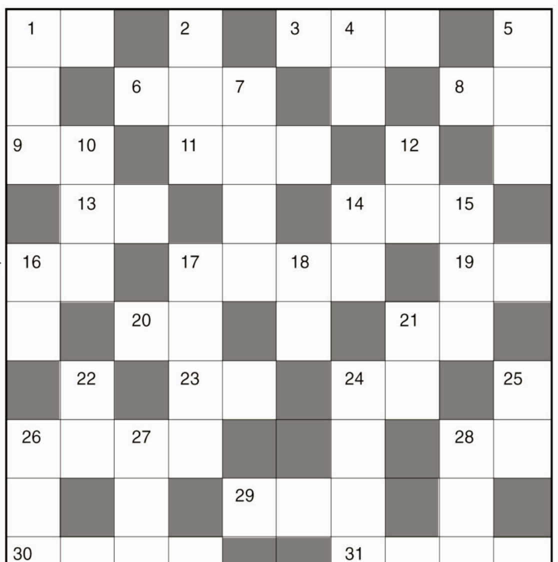

बायें से दायें:-

1. ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया की 'झूठ बोले कौआ काटे' गीत वाली फिल्म-2
3. 'तुम रूठ के मत जाना' गीत वाली भारत भूषण, मधुबाला अभिनीत फिल्म-3
6. अनिल, माधुरी की 'कह दो कि तुम' गीत वाली फिल्म-3
8. 'कहां गए ममता भरे दिन' गीत वाली सुनील शेट्टी, रंभा की फिल्म-2
9. बी.आर. चोपड़ा की बहु सितारा फिल्म 'वक्त' के संगीत निर्देशक कौन थे-2
11. नायक अनिलकपूर की पहली फिल्म-3
13. राजेश खन्ना, राखी, शर्मिला की 'मेरे दिल में आज क्या है' गीत वाली फिल्म-2
14. 'दिल क्यों धड़कता है' गीत वाली फिल्म-3
16. सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा की फिल्म-2
17. 'नाजुक सी कली थी' गीत वाली अजय देवगन, मनीषा, अविनाश वधावन, करिश्मा की फिल्म-4
19. 'हम तो तंबू में बंबू' गीत वाली फिल्म-2
20. 'समय तू जल्दी जल्दी चल' गीत वाली राजेश खन्ना, शबाना, विद्या सिन्हा की फिल्म-2
21. 'बाबुल का ये घर बहना' गीत वाली फिल्म-2
23. फिल्म 'शोले' में धर्मेन्द्र के किरदार का क्या नाम था ?-2
24. विकास भल्ला, सुमित सहगल, नीलम की फिल्म-2
26. 'बाबूजी धीरे चलना' गीत वाली गुरु दत्त, शकीला, श्यामा की फिल्म-2,2
28. आफताब, उर्मिला की 'रुकी- रुकी सी जिंदगी' गीत वाली फिल्म-2
29. सुनील दत्त, आशापारेख की फिल्म-3
30. 'चोरी चोरी ओ गोरी' गीत वाली फिल्म-4
31. फिल्म 'डोली सजा के रखना' के संगीत निर्देशक कौन हैं ?-4

ऊपर से नीचे:-

1. जे. पी. दत्ता की 'ऐ जाते हुए लम्हों' गीत वाली एक मल्टी स्टार फिल्म-3
2. फारुख शेख, नसीरुद्दीन, स्मिता की फिल्म-3
4. 'इतनी शक्तिहमें देना दाता' गीत वाली जया भादुड़ी की पहली फिल्म-2
5. सुनील दत्त, वैजयंती माला की 'औरत ने जनम दिया मर्दों को' गीत वाली फिल्म-3
7. संजीव कुमार, तनूजा की 'आया रे खिलौने वाला' गीत वाली फिल्म-4
10. 'कभी खोले ना तिजोरी का ताला' गीत वाली जीतेंद्र, लीना चंदावरकर की फिल्म-3
12. रामगोपाल वर्मा की मनोज वाजपेयी, उर्मिला की जोड़ी वाली एक सस्पेंस फिल्म-2
14. अजय देवगन, ट्विंकल खन्ना की 'मेरे सीने में तेरा दिल धड़के' गीतवाली फिल्म-2
15. धर्मेन्द्र, सुचित्रा सेन अभिनीत फिल्म-3
16. बलराज साहनी, पंढरी बाई, नंदा की 'टाई लगा के बन गए जनाब हीरो हीरो' गीतवाली फिल्म-2
17. धर्मेन्द्र, जीतेंद्र, हेमा, जीनत की फिल्म-4
18. फिल्म 'एक दूजे के लिये' में कमल हासन के किरदार का नाम क्या था ?-2
21. अमजद खान, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी की 'पर्दे में कोई बैठा है' गीत वाली फिल्म-2
22. 'मैं नये जमाने की लैला' गीत वाली अजय देवगन, रवीना टंडन की फिल्म-2
24. अमिताभ बच्चन, नूतन, पद्मा खन्ना की 'तेरा मेरा साथ रहे ' गीत वाली फिल्म-4
25. 'दुनिया जब जलती है' गीत वाली धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की फिल्म-2
26. राज कपूर, नर्गिस की 'आ जाओ तड़पते हैं अरमां' गीत वाली फिल्म-3
27. 'चलो दिलदार चलो' गीत वाली फिल्म-3
28. फिल्म 'ये तेरा घर ये मेरा घर' में सुनील शेट्टी के साथ नायिका कौन है ?-3

फिल्म वर्ग पहेली-2085

15 दिन में 13वीं बार की गई बढ़ोतरी

ट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा

नई दिल्ली । पेट्रोल-डीजल की कीमत में तेजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। इस तरह 15 दिन में 13वीं बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 104.61 रुपए और डीजल की कीमत 95.87 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल-डीजल की कीमत में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का ताजा सिलसिला 22 मार्च को शुरू हुआ था। इस दौरान 24 मार्च और एक अप्रैल को छोड़कर हर दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 13 किस्तों में क्रमशः 80, 80, 80, 80, 50, 30, 80, 80, 80, 80, 80, 40 और 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह 13 किस्तों में यह 9.20 रुपए बढ़ चुका है। इससे पहले चार नवंबर से 21 मार्च तक पेट्रोल-डीजल का दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस तरह से 22 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 9 रुपए 20 पैसे की वृद्धि की गई है। यह आम आदमी की जेब पर सीधी चोट है। इस वृद्धि के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों को माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण ईंधन खुदरा विक्रेताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई के लिए यह वृद्धि जरूरी है। पिछले साल सितंबर के बाद पेट्रोल के मुकाबले डीजल का बाजार ज्यादा तेज हुआ था। कारोबारी लिहाज से देखें तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल बनाना महंगा पड़ता है। लेकिन भारत के खुले बाजार में पेट्रोल महंगा बिकता है और डीजल सस्ता बिकता है। पिछले 22 मार्च से डीजल 13 किस्तों में 9.20 रुपये महंगा हो गया है। मूडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए तेल कंपनियों आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की थी जिससे उन्हें 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

गौतम अडानी की संपत्ति में 28.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी

मुंबई । दिग्गज भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई, इसकारण ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में 4.69 अरब डॉलर यानी करीब 35,408 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक अडानी 105 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर बने हुए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 28.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो दूसरे टॉप रईसों के मुकाबले सबसे अधिक है। सोमवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी अडानी ग्रीन एनर्जी में रही। कंपनी का शेयर नौ फीसदी की छलांग के साथ बंद हुआ। अडानी टोटल गैस के शेयरों में 5.43 फीसदी, अडानी पोर्ट में 4.20 फीसदी, अडानी पावर के शेयरों में 4.11 फीसदी, अडानी विल्मर में 1.70 फीसदी, अडानी एंटरप्राइजेज में 1.04 फीसदी और अडानी ट्रांसमिशन में 1.02 फीसदी की तेजी आई। इस बीच देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर बने हुए हैं। सोमवार को उनकी नेटवर्थ में 94.6 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और उनकी नेटवर्थ 100 अरब डॉलर पहुंच गई। इस साल अंबानी की नेटवर्थ में 9.97 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अडानी और अंबानी की नेटवर्थ में अब पांच अरब डॉलर का अंतर हो चुका है। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 288 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक अमेजान के फाउंडर जेफ बेजोस 193 अरब डॉलर की नेटवर्थ के फ्रांसीसी बिजनसमैन और दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल नंबर पर बने हुए हैं।

फिर आसमान पर पहुंचे फलों और हरी सब्जियों के दाम, भिंडी 120 रुपये और 100 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा

नई दिल्ली । देश के कई हिस्सों में नवरात्र के दौरान फलों और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। विशेष रूप से हरी सब्जियों के दामों में पिछले दो-तीन दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फलों और सब्जियों के बढ़ते दाम ने हर घर के बजट को बिगाड़ दिया है। कुछ सब्जियों के दाम तो फलों से भी महंगे हो गए हैं। एक नींबू 10 रुपये में बिक रहा है। वहीं, अगर एक किलो नींबू खरीदने जाते हैं तो दुकानदार 200 से 250 रुपये प्रति किलो की मांग कर रहे हैं। हालांकि, थोक मंडियों में नींबू के दाम काफी कम हैं। इसी तरह भिंडी, परवल, खीरा, घीया, तोरई समेत कई और सब्जियां भी रुला रही है। भिंडी 120 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं करेला 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच बिकने लगे हैं। अमूमन नवरात्र में प्याज के दाम घट जाते हैं, लेकिन इस बार प्याज भी 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जमाखोरी और ट्रांसपोर्टेशन खर्च में बढ़ोतरी से कई तरह के सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। गाजर 50 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। अदरक 70 से 80 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 90 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसी तरह नवरात्र में सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से यातायात किराया बढ़ जाने से ये हालात पैदा हुए हैं। अगले 15 दिनों तक त्योहारों का सीजन खत्म हो जाने के बाद भी महंगाई खत्म नहीं होने वाली है। फलों और सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे महंगाई की मार लोगों पर साफ नजर आ रही है। सब्जियां लगातार लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। देश के हर कोने में खाद्य पदार्थों की चीजों में बढ़ोतरी ने रसोई घर का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम के बाद सब्जियों के दाम जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, टमाटर की कीमत की अगर बात करें तो 2 महीने पहले तक जहां टमाटर की कीमत 20 रुपये किलो थी । वह पिछले कुछ दिनों में

टोयोटा की मार्च में बिकीं सबसे ज्यादा कारें

नई दिल्ली । पिछले महीने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी ने 17,131 कारें बेची हैं, जो कि 14 फीसदी की सालाना ग्रोथ के साथ है। टोयोटा ने फरवरी में 8,745 कारें ही बेची थीं, ऐसे में मार्च में करीब 90 फीसदी सेल बढ़ी है। कंपनी ने पिछले महीने, यानी मार्च 2022 कार सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। बीते 5 साल के दौरान टोयोटा ने किसी महीने में सबसे ज्यादा कारें बेची हैं, तो वह मार्च 2022 ही है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर भारत में हालिया लॉन्च नई ग्लैंजा के साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर, टोयोटा कैम्री सेडान और इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर जैसी एमपीवी और एसयूवी कारें बेचती हैं। चलिए, आज हम आपको टोयोटा इंडिया की मार्च 2022 सेल्स रिपोर्ट डिटेल में बताते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने साल 2021-22 में साल 2020-21 के मुकाबले 58 फीसदी की ग्रोथ दर्ज कराते हुए कुल 123,770 कारें बेची हैं। साल 2020-21 में कंपनी ने महज 78,262 कारें बेची थीं, ऐसे में पिछला वित्तीय वर्ष टोयोटा के लिए काफी अच्छा रहा। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लंबे समय से कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार के रूप में उभरकर सामने आई है। बीते मार्च में इनोवा क्रिस्टा की 8000 यूनिट तक बिकने की संभावना है। इसके साथ ही फॉर्च्यूनर की भी अच्छी बिक्री होती है। हालिया लॉन्च नई ग्लैंजा को लेकर भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच टोयोटा अर्बन क्रूजर और कैम्री जैसी कारें भी लोगों की फेवरेट है। नई ग्लैंजा और हाइलक्स से कंपनी मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में लगी है। आने वाले समय में कंपनी मिडसाइज एसयूवी के साथ ही सस्ती एमपीवी भी लॉन्च कर सकती है।आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत होते ही टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 1 अप्रैल 2022 से अपनी सभी कारों की कीमत में 4 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है।

संक्षिप्त समाचार

पैन को आधार से लिंक कराने की तिथि निकली, जुर्माना देकर अब भी करा सकेंगे लिंक

नई दिल्ली । पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी। इस तारीख तक भी बहुत से लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। अब अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। हालांकि, सरकार ने अब भी पैन धारकों की सुविधा के लिए आधार से लिंक न हुए पैन को निष्क्रिय नहीं किया है। अब पेन एक्टिवेट तो रहेगा, लेकिन वह भी केवल 31, मार्च 2023 तक। लेकिन, दिक्कत यह है 31 मार्च, 2022 के बाद जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, वो बहुत से कामों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए पैन को जितनी जल्दी हो आधार से लिंक जरूर करा लेना चाहिए। 31 मार्च के बाद भी पैन को आधार से लिंक तो कराया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए जुर्माना देना होगा। पहले यह निःशुल्क हो रहा था। अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक कराने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा और इसके बाद जुर्माना राशि बढ़कर एक हजार रुपये हो जाएगी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी, 2022 तक 43.34 करोड़ पैन आधार के साथ लिंक हो गए थे। लेकिन, अब भी बहुत से लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसलिए सरकार ने जुर्माना भरकर यह काम करने की सुविधा दी है।

इरेडा ने वित्त वर्ष 2021-22 में 23,921 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए

नई दिल्ली । देश की सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास निगम (इरेडा) ने वित्त वर्ष 2021-22 में रिकार्ड 23,921.06 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दी जिसमें करीब 16,070.82 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, '...नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर्ज देने वाली संस्था इरेडा ने 2021-22 में अब तक के सर्वाधिक 23,921.06 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दी। इसमें से करीब 16,070.82 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।' इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने कर्मचारियों के साथ बातचीत में कहा कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद एजेंसी ने 2021-22 में उल्लेखनीय लक्ष्य हासिल किए हैं।

टीवीएस की बाइक, स्कूटर के एक्सपोर्ट में आई कमी

नई दिल्ली । आटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी टीवीएस मोटर ने मार्च 2021 के मुकाबले टीवीएस की मार्च 2022 में अपनी बाइक और स्कूटर के एक्सपोर्ट में भी कमी देखने को मिली है। टीवीएस मोटर कंपनी ने मार्च 2022 बाइक सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। टीवीएस ने बीते मार्च 307,954 मोटरसाइकल, स्कूटर, मोपेड और थ्री-व्हीलर्स बेचे, जिनमें एक्सोर्ट भी शामिल है। टीवीएस भारत में अपाचे सीरीज बाइक्स के साथ ही रेडर 125 बाइक और टीवीएस जुपिटर स्कूटर समेत अन्य पॉपुलर मोटरसाइकल और स्कूटर बेचती है।टीवीएस की मार्च 2021 टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सेल्स रिपोर्ट देखें तो कंपनी ने पिछले महीने कुल 292,918 टू-व्हीलर्स बेचे, जो कि मार्च 2021 के 3,22,643 यूनिट के मुकाबले कम है। टीवीएस ने मार्च में 1,57,254 मोटरसाइकल के साथ ही 94,747 यूनिट स्कूटर और मोपेड बेचे। वहीं, 109,724 यूनिट बाइक और स्कूटर विदेशों में निर्यात किए गए। थ्री-व्हीलर्स की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में टीवीएस कंपनी ने पिछले महीने घरेलू और इंटरनैशनल मार्केट में कुल 15,036 यूनिट बेचे। सालाना रूप से टीवीएस के अलग-अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स की बिक्री में पिछले महीने कमी देखने को मिली है। टीवीएस ने हर सेगमेंट में लोगों के लिए सस्ते और महंगे मोटरसाइकल और स्कूटर पेश किए हैं। टीवीएस ने आईक्यूब जैसा पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेश किया है। इस साल टीवीएस एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है, जिसकी रेंज आईक्यूब के मुकाबले बेहतर होगी। बता दें कि भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस अपाचे सीरीज की पॉपुलर बाइक्स के साथ ही हालिया लॉन्च रेडर 125 समेत अन्य कई धांसू बाइक्स पेश बाइक्स पेश की हैं।

सेबी ने डिजिटल फॉरेंसिक एजेंसी के चयन के लिए मंगाए आवेदन

नयी दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) तलाशी एवं जब्ती अभियानों के दौरान घटनास्थल से डेटा जुटाने में मदद के लिए एक एजेंसी को नियुक्त करने की तैयारी में है। इसके लिए सेबी ने मोबाइल, कंप्यूटर एवं टैबलेट जैसे उपकरणों से डिजिटल सबूतों को जब्त करने, उन्हें फिर से निकालने और उनका विश्लेषण करने के लिए अनुभवी डिजिटल फोरेंसिक एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाजार नियामक ने यह कदम कई संस्थाओं द्वारा टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर कथित रूप से धोखाधड़ी किए जाने की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। सेबी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि डेटा फॉरेंसिक एजेंसी को तलाशी एवं जब्ती के दौरान तलाशी लेने गई टीम और घटनास्थल से डेटा जब्त करने में सहायता देनी होगी। इसके अलावा इस एजेंसी को कई तरह के डिजिटल उपकरणों जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, सीडी/डीवीडी, सर्वर आदि को फॉरेंसिक इस्तेमाल के लिए जब्त भी करना होगा। लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, सीडी/डीवीडी, सर्वर आदि को फॉरेंसिक इस्तेमाल के लिए जब्त भी करना होगा। सर्वर आदि को फॉरेंसिक इस्तेमाल के लिए जब्त भी करना होगा। नियामक के अनुसार इच्छुक फॉरेंसिक एजेंसियां 26 अप्रैल तक आवदेन कर सकती है।

सीसीआई ने स्विगी और जोमैटो के खिलाफ 60 दिन में जांच करने का दिया आदेश

नई दिल्ली । ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी और जोमैटो के खिलाफ उनके रेस्टोरेंट भागीदारों के साथ अनुचित तरीके से कारोबार करने के का आरोप है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दोनों कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को लेकर जांच का आदेश दिया है। यह आदेश नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की शिकायत के बाद दिया गया है। एनआरएआई देशभर में 50000 से ज्यादा रेस्टोरेंट ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करता है। सीसीआई ने 4 अप्रैल को आदेश दिया कि स्विगी और जोमैटो के खिलाफ लग रहे पेमेंट साइकिल में देरी, एकतरफा क्लॉज और कमीशन लगाने जैसे आरोपों की एक जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष ट्रेड रेगुलेटर ने अपने महानिदेशक को आरोपों की गहन जांच करने और 60 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है।

लाइव मिंट के मुताबिक, सीसीआई ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह हितों के टकराव का मामला लग रहा है। रेस्टोरेंट भागीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा पर इसके असर की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। सीसीआई ने कहा कि दोनों ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली प्रमुख कंपनियां हैं। बाजार में अपनी मजबूत पकड़ के कारण ये दोनों प्रतिकूल असर डाल सकती हैं। कामकाज के समान अवसरों को भी अपने हिसाब से प्रभावित कर सकती हैं। सीसीआई का कहना है कि स्विगी और जोमैटो अपनी बाजार हिस्सेदारी या राजस्व हितों वाले रेस्टोरेंट भागीदारों को अन्य के मुकाबले ज्यादा तवज्जो देती हैं। ऐसा व्यवहार कई तरीकों से हो सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। आयोग ने कहा कि जोमैटो और स्विगी के समझौतों में शामिल 'मूल्य समानता उपनियम' व्यापक अंकुशों की ओर इशारा करते हैं। इन नियमों के तहत रेस्टोरेंट भागीदार अपने खुद के किसी भी माध्यम के जरिये कम दाम पर डिलीवरी नहीं कर सकते या ज्यादा छूट नहीं दे सकते हैं। इससे पहले एसोसिएशन ने पिछले साल जुलाई में स्विगी और जोमैटो के खिलाफ डाटा मास्किंग, डीप डिस्काउंटिंग और प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी के उल्लंघन के आरोपों की जांच की मांग की थी। उसका दावा था कि महामारी के दौरान दोनों कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एनआरएआई ने आरोप लगाया कि स्विगी और जोमैटो रेस्टोरेंट से 20 से 30 फीसदी तक कमीशन लेते हैं, जो अव्यवहार्य और ज्यादा है।

एसबीआई योनो उपभोक्ताओं के लिए लाया 'सुपर सेविंग डेज़' में धमाकेदार ऑफर

नई दिल्ली । भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के मोबाइल एप योनो के यूज़र्स के लिए खुशखबरी है। योनो अपने उपभोक्ताओं के लिए 'सुपर सेविंग डेज़' में धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। योनो अपने ग्राहकों को कुछ बड़े ब्रैंड्स से शॉपिंग करने पर 45 फीसदी की छूट उपलब्ध करवा रहा है। इस ऑफर का लाभ आप 7 अप्रैल 2022 तक उठा सकते हैं। योनो ने ट्विटर पर यह जानकारी देते हुए बताया है कि यूजर्स एमेजॉन, लाइफस्टाइल, ओयो, आजिओ, ईज माय ट्रिप, वेदांतु और महिंद्रा से योनो के ज़रिए शॉपिंग कर भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एमेजॉन डॉट इन से योनो के माध्यम से शॉपिंग करने पर आपको फ्लैट 2I5 फीसदी की छूट मिल सकती है। वहीं, आजिओ पर आपको अधिकतम 500 रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। योनो के जरिए ओयो का इस्तेमाल करने आपको फ्लैट 45 फीसदी की छूट मिलेगी। जबकि ईज माय ट्रिप आपको अधिकतम 850 रुपए की छूट देगा। योनो से खरीदारी पर लाइफस्टाइल स्टोर्स आपको अतिरिक्त 20 फीसदी की छूट देंगे। वहीं, वेदांतु आपको फ्लैट 25 फीसदी की छूट देगा। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको योनो से शॉपिंग करने पर कार लोन पर संबंधी बेनेफिट्स और कुछ शर्तों के साथ कार की एक्सेसरिज़ पर छूट दे रही है। अगर आप एसबीआई कस्टमर हैं तो अपने फोन में पहले एसबीआई योनो ऐप डाउनलोड करें फिर शॉप एंड ऑर्डर पर क्लिक करें। इसके बाद योनो सुपर सेविंग डेज़ का इस्तेमाल कर शॉपिंग करें।

एसबीआई ने कहा है कि वह भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहता है और इसी दिशा में कदम उठाते हुए योनो ऐप को एक अलग डिजिटल एंटटी बना रहा है। बैंक का कहना है कि वह नई एंटिटी का वनली योनो रखेगा। एसबीआई मौजूदा योनो ग्राहकों को नई एंटिटी में माइग्रेट कर देगा और बैंक का मानना है कि वह इस कार्य को 12 से 18 महीनों में अंजान देगा।

टाटा हाउसिंग प्रीमियम आवास, प्लाट परियोजनाओं के लिए 1,200 करोड़ रुपए निवेश करेगी

नई दिल्ली । टाटा समूह की रियल एस्टेट शाखा टाटा हाउसिंग ने अगले दो वर्षों में भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी खुद और संयुक्त उद्यमों के जरिए प्रमुख शहरों में भूमि अधिग्रहण करेगी तथा यहां समूह आवास परियोजनाओं के साथ ही प्लॉट डेवलपमेंट की योजना है। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सीईओ और एमडी संजय दत्त ने कहा कि महामारी के दौरान प्लॉट की मांग में काफी वृद्धि हुई है और कंपनी ने बेंगलुरु में सभी 157 भूखंडों को 130 करोड़ रुपए में बेचा है। टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टाटा संस की 100 प्रतिशत सहायक कंपनियां हैं। टाटा हाउसिंग ने हाल ही में बेंगलुरु के देवनहल्ली में एक परियोजना 'स्वरम शुरू की है। परियोजना की शुरुआत के 36 घंटों के भीतर सभी प्लॉट बिक गए। उन्होंने कहा, ''हमने सभी 157 भूखंड 130 करोड़ रुपये में बेचे। यह परियोजना टाटा हाउसिंग की 140 एकड़ की टाउनशिप कर्नाटिका का हिस्सा है, जिसे वन बैंगलोर लक्जरी प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने विकसित किया है, जो टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और एमएस रमैया रियल्टी एलएलपी के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

मार्च में रॉयल एनफील्ड ने कुल 67,677 यूनिट बेची

नई दिल्ली । बीते मार्च महीने में रॉयल एनफील्ड बाइक्स की सालाना बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, वहीं मंथली सेल भी बढ़ी है। देसी कंपनी रॉयल एनफील्ड ने मार्च में कुल 67,677 यूनिट मोटरसाइकल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेची है। घरेलू मार्केट में रॉयल एनफील्ड बाइक्स की मार्च 2021 के मुकाबले इस साल मार्च में बिक्री घटी है। हालांकि, एक्सपोर्ट में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिली है और जहां साल 2020-21 में कंपनी ने 38,622 यूनिट एक्सपोर्ट किए थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 81,032 मोटरसाइकल्स बाहरी देशों में निर्यात किए। क्लासिक 350, मीटियॉर 350 और हिमालयन समेत अन्य बाइक्स की देश-विदेश में बंपर बिक्री होती है। मार्च 2022 रॉयल एनफील्ड बाइक्स सेल्स रिपोर्ट देखें तो कंपनी ने पिछले महीने डोमेस्टिक और इंटरनैशनल मार्केट में कुल 67,677 मोटरसाइकल बेचे। जहां घरेलू बाजार में 58,477 यूनिट बिकी, जो कि मार्च 2021 के मुकाबले 3 फीसदी कम है। वहीं, 9,200 बाइक्स एक्सपोर्ट किए गए और यह मार्च 2021 के मुकाबले 56 फीसदी ज्यादा है। साल 2021-22 वित्तीय वर्ष में रॉयल एनफील्ड ने घरेलू मार्केट में कुल 5,73,728 बाइक्स बेचे और यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुकाबले 9 फीसदी कम है। हालांकि, इसी अवधि में एक्सपोर्ट में 110 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। विदेशों में मीटियॉर 360 और क्लासिक 350 जैसी बाइक्स की अच्छी डिमांड है। रॉयल एनफील्ड ने बीते साल अपनी दो सबसे पावरफुल बाइक्स के एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किए और लिमिटेड एडिशन ये बाइक्स मिनटों में बिक गईं। रॉयल एनफील्ड इस साल हंटर 350, सुपर मीटियॉर 650 और शॉटगन 650 के साथ ही और भी कई बाइक्स इंडियन मार्केट में पेश कर सकती है।

बता दें कि रॉयल एनफील्ड भारत में 350 सीसी से लेकर 650 सीसी तक की बाइक्स बेचती है, जिनमें बेस्ट सेलिंग बाइक क्लासिक 350 के साथ ही बुलेट 350, एलेक्ट्रा 350, मीटियॉर 350, हिमालयन, स्क्रैम 411, इंटरसेप्टर 650 और कंटिनेंटल जीटी 650 जैसी बाइक्स बेचती है।

टोयोटा एमपीवी सेगमेंट में करेगी नई कार लॉन्च

नई दिल्ली । टोयोटा कंपनी अब किफायती एमपीवी सेगमेंट में अपनी नई कार लॉन्च करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि आने वाले समय में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर भारत में एक नई एसयूवी से साथ ही एक नई एमपीवी भी लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि टोयोटा और सुजुकी जॉइंट वेंचर में नई मिडसाइज एसयूवी लाने की तैयारी में है, जिसे फिलहाल टोयोटा डी22 कोडनेम से पेश किया जा सकता है। इस मिडसाइज एसयूवी को डायहात्सु न्यू जेनरेशन आर्किटेक्चर प्लैटफॉर्म पर डिवेलप किया जाएगा। यह एसयूवी इस साल दीवाली तक लॉन्च की जा सकती है। टोयोटा की इस मिडसाइज एसयूवी के एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक टोयोटा कोरोला क्रॉस की छाप देखने को मिल सकती है। वहीं, फीचर्स की बात करें तो टोयोटा की अपकमिंग मिडसाइज एसयूवी में हाइब्रिड टेक्नॉलजी के साथ ही अडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम समेत कई खास खूबियां देखने को मिल सकती हैं। टोयोटा आने वाले समय में भारत में मारुति अर्टिगा और किआ कारेन्स समेत अन्य पॉपुलर कंपनियों की अच्छी बिक्री वाली 7 सीटर सस्ती एमपीवी को चैलेंज करने के लिए नई एमपीवी टोयोटा रूमियन लॉन्च कर सकत है। इस एमपीवी में 1.5 लीटर 4 सिलिंडर नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि 105बीएचपी की पावर और 138 एनएम टॉर्क जेनरेट करेगा। इस एमपीवी को भी 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि टोयोटा ने हाल ही में अपनी हैचबैक ग्लैंजा का अपडेट कर इसे न्यू टोयोटा ग्लैंजा के रूप में पेश किया है। यह हैचबैक अब बेहतर लुक और फीचर्स से लैस है।

गुजरात चुनाव में बहुमत नहीं तो आप को 50 से अधिक सीटें जरूर मिलेंगी : संदीप पाठक

अहमदाबाद । पंजाब में शानदार सफलता से गदगद आम आदमी पार्टी (आप) को गुजरात विधानसभा के चुनाव में अपने लिए अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं7 आप का दावा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत नहीं तो 50 अधिक सीटों पर जीत जरूर मिलेगी7 गुजरात आप के प्रभारी संदीप पाठक का दावा है कि अगर राज्य में अभी चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी 58 सीटें जीत सकती है7 एक एजंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में आप 55 सीटें जीत सकती है7 जबकि हमारे आंतरिक सर्वे में आम आदमी पार्टी को 58 सीटें मिलने की संभावना है7 संदीप पाठक ने कहा कि गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस मौजूदा समय में भाजपा को हरा नहीं सकती7 इसलिए गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को एक अच्छा विकल्प मानते हैं7 उन्होंने कहा कि हम यहां किसी पार्टी को हराना नहीं चाहते बल्कि यह चाहते हैं कि गुजरात के लोगों की जीत हो7 गुजरात के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। पाठक ने कहा कि एक समय था जब गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं7 आप की नजर उन इलाकों पर है जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भाजपा पर भरोसा नहीं करते। हम ऐसे लोगों के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप पाठक ने कहा कि वैसे गुजरात विधानसभा के चुनाव दिसंबर तक होंगे, परंतु कुछ जानकारों के मुताबिक राज्य में चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। गौरतलब है पंजाब की जीत के रणनीतिकार माने जाते संदीप पाठक दिल्ली आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। गौरतलब है पंजाब की जीत के रणनीतिकार माने जाते संदीप पाठक दिल्ली आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आप को मिली एकतरफा जीत का श्रेय संदीप पाठक की रणनीति को दिया जाता है। संदीप पाठक अब पंजाब की रणनीति पर गुजरात में करना चाहते हैं। संदीप पाठक का कहना है कि जो लोग अच्छी स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं गुजरात में चाहते हैं, उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। उनका यह भी कहना है कि गुजरात और पंजाब में काफी समानता है और दोनों ही राज्य तरक्कीपसंद हैं तथा दोनों को बदलाव की जरूरत है।

भगवा रंग की टोपी और पीएम की फोटो वाली चाकलेट के साथ दिखे भाजपा सांसद

नई दिल्ली । भाजपा की मंगलवार सुबह संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक में भाजपा के तमाम सांसद मौजूद रहे। बैठक के दौरान अलग नजारा देखने को मिला। पार्टी के कई सांसदों ने भगवा रंग की टोपी पहनी हुई थी। बताया जा रहा है कि ये वहां ही टोपी है, इस पीएम नरेन्द्र मोदी ने बीते महीने अहमदाबाद रोड शो में पहना था। खबर के मुताबिक, भाजपा सांसदों को चाकलेट भी दी गई। चाकलेट के रैपर पर पीएम मोदी की तस्वीर छपी थी। बताया जा रहा है कि इस टोपी को गुजरात भाजपा इकाई ने तैयार करवाया है। टोपियों को संसदीय दल की बैठक में आए भाजपा सांसदों में बांटा गया था। टोपी पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का निशान था। इसके अलावा सांसदों को चाकलेट भी दी गई। टोपी का डिजाइन उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी से लिया है। उत्तराखंड की टोपी पर ब्रह्मकमल अंकित होता है। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राजकीय फूल है। मोदी ने उत्तराखंडी टोपी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पहना था। इसके बाद से टोपी की डिमांड काफी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने बैठक में 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पर चर्चा की। भाजपा ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन से होगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने नौ दिनों के लिए तय कार्यक्रम पर भाजपा सांसदों से चर्चा की। भाजपा के एक सांसद ने कहा कि पीएम ने पोषण अभियान जैसे कई सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी बात की। उन्होंने हम सभी से पोषण अभियान और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार करने के लिए कहा गया है।

कर्नाटक सरकार में बदलाव के आसार

नई दिल्ली । कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले ही प्रदेश भाजपा में गतिविधियां तेज हो गई हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कैबिनेट में बदलाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। वह राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। राज्य में अप्रैल 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं, इस सियासी उठा पटक के बीच राज्य के कई भाजपा नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा डाल लिया है। बोम्मई ने कहा, मैंने नड्डा जी और अमित शाह जी से मुलाकात के लिए समय मांगा है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलना अभी बाकी है। अगर समय मिलेगा तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। भाजपा सूत्रों के हवाले से लिखा कि कैबिनेट में जगह पाने की संभावनाएं और बाहर होने का डर लेकर कई मंत्री और नेता भी दिल्ली पहुंच गए हैं। हाल के हफ्तों में बोम्मई ने कहा कि वह अप्रैल की शुरुआत में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान कैबिनेट विस्तार पर अंतिम फैसला ले लेंगे। खास बात है कि वे दिल्ली भी ऐसे समय पर पहुंच रहे हैं, जब भाजपा संसदीय दल की बैठक हो रही है। फिलहाल, कर्नाटक 34 मंत्रियों वाली कर्नाटक सरकार में चार पद रिक्त हैं। अटकलें हैं कि पार्टी नए चेहरों को शामिल करने के लिए कम से कम चार मंत्रियों को बाहर कर सकती है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि भाजपा 2023 चुनाव से पहले नए पार्टी अध्यक्ष नए पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर रही है। बोम्मई ने कहा, मुझे कैबिनेट विस्तार के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार मैं दिल्ली जाऊंगा और नड्डा जी और अमित जी से मिल लूंगा, तो संभावना है कि कुछ स्थिति साफ हो जाए।

कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति से वंचित न रह जाएं। कोर्ट इस तरह के बच्चों की स्थिति पर खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट बच्चों की शिक्षा जारी रखने और उनकी दूसरी जरूरतों का ध्यान रखने का राज्यों को निर्देश दे चुका है। मामले में एमिकस क्यूरी की हैसियत से कोर्ट की सहायता कर रहे वकील गौरव अग्रवाल ने आशंका जताई थी कि माता-पिता पर बकाया कर्ज़ की वसूली के लिए वित्तीय संस्थान संपत्ति पर कब्ज़ा कर सकते हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्यों को इस पहलू पर गौर करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार से संरक्षण आयोग की तरफ से रखी गई रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। बताया है देशभर में कोरोना के चलते 10,793 बच्चों ने दोनों अभिभावकों को खोया है। 1,51,322 बच्चों के माता-पिता में से एक की मृत्यु इस बीमारी से हुई है। आयोग ने यह भी बताया है कि राज्यों ने इन बच्चों की स्थिति जानने के लिए सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अब तक पूरी नहीं की है। कोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए राज्यों को प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कहा।

तब्लीगी जमात के मामले में दिल्ली पुलिस के पास जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका

नई दिल्ली । कोरोना महामारी के दौरान विदेश से निजामुद्दीन मरकज में आए तब्लीगी जमात के सदस्यों को अपने घर में शरण देने के मामले में दर्ज एफआइआर मामले में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आखिरी मौका दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने अदालत के आदेश के बावजूद भी लिखित जवाब नहीं दाखिल करने पर सवाल उठाया। साथ ही पुलिस को आखिरी मौका देते हुए सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता अशिमा मंडला ने पीठ को बताया कि पुलिस ने अदालत के निर्देश के बावजूद भी लिखित बयान नहीं दिया है। पिछली सुनवाई पर पीठ ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या गत वर्ष तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वैध वीजा पर आए विदेशियों को भारतीय नागरिकों द्वारा अपने घर में शरण देने पर कोई प्रतिबंध लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने देशव्यापी लाकडाउन के दौरान जमातियों को अपने घर में पनाह देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी रद करने की मांग करते हुए कहा है कि लाकडाउन के कारण यात्रा नहीं करने वालों को उन्होंने शरण दी थी। पुलिस ने गलत तरीके से यह मामला दर्ज किया है। लुटियंस दिल्ली इलाके से वाहन चोरी करने वाले एक बदमाश को नई दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। आरोपित की पहचान अजय उर्फ आदेश के तौर पर हुई है। उसके कब्जे से चोरी की स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। आरोपित पर पहले से चार मामले दर्ज हैं। डीसीपी अमृता गुगुलोथ के मुताबिक तुगलक लेन स्थित जेजे कैंप निवासी चंदन शाह ने तुगलक रोड थाने में अपनी स्विफ्ट डिजायर कार चोरी होने की शिकायत दी थी। जांच टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर एक संदिग्ध की पहचान की।

पाकिस्तान और श्रीलंका की जगह नेपाल नहीं फंसा ड्रैगन के जाल में

नई दिल्ली । नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा पिछले सप्ताह भारत आए थे,तब उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में बताया था कि कैसे उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कह दिया कि हमें लोन की नहीं अनुदान की जरूरत है। देउबा ने कहा था कि हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए चीन से कर्ज की जरूरत नहीं है। तथ्य यह है कि चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत नेपाल ने कोई भी करार नहीं किया और काठमांडू से वांग यी खाली हाथ ही लौट आए। नेपाल के फैसले को दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुकाबले समझदारी भरा ही कहा जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में आज जो अस्थिरता और आर्थिक संकट के हालात हैं। उसकी एक वजह चीन को भी माना जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जो कुल कर्ज है, उसमें 10 फीसदी हिस्सा चीन का ही है। आज इमरान खान चीन के बेहद करीबी हैं, और सेना अमेरिका के सुर में बात करती दिख रही है। नतीजा यह है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई है। श्रीलंका की स्थिति बेहद विपरीत है, जहां उसके पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है और बत्ती गुल है। महिंदा राजपक्षे की सरकार गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। कहा जा रहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए उन्होंने चीन से ऊंची ब्याज दर पर जो लोन लिए थे, इसकारण देश की कमर टूट गई है। फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, ताकि लोगों को आंदोलन करने से रोका जा सके ।

दिवंगत पिता के नाम आवंटित बंगले से निकाले जाने पर बोले चिराग पासवान

नई दिल्ली । अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को राष्ट्रीय राजधानी में आवंटित बंगला '12 जनपथ से बेदखल किये गये जाने के बाद लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जो चीज सरकारी है, उसके साथ किसी तरीके का मोह रखना गलत है। मुझे मेरा सौभाग्य था कि मुझे इतने समय तक उस घर में रहने का अवसर मिला। उस घर में मेरे पिताजी ने न सिर्फ राजनीतिक जीवन की एक लंबी पारी खेली, बल्कि सामाजिक न्याय की वह जन्म भूमि रही है। उसी घर में पापा ने पार्टी बनाई थी। उसी घर में ऊंची जाति के जो गरीब थे, उनको आरक्षण देने की सोच रखी गई थी। जब लॉकडाउन लगा था और पापा उस घर में तस्वीरें देखते थे कि मजदूर जा रहे हैं, उनको इस बात की चिंता सताती थी कि वह खाना कैसे खाएंगे। चिराग ने कहा कि घर का मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल ये घर मुझे खाली करना ही था। जो घर खाली करवाने का तरीका था, मुझे उस तरीके से दिक्कत है। घर खाली करवाते समय मेरे पिताजी की तस्वीरों को फेंका गया। घर के कोने-कोने में जिन महापुरुषों की तस्वीरें लगी थीं, उन्हें जिस तरीके से सड़क पर फेंका गया, मुझे उससे दिक्कत है। मेरे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि मैं 29 तारीख की रात में घर को खाली करने के लिए तैयार था। मुझे नहीं पता, क्यों मुझे बुला के वादा किया गया? क्यों केंद्रीय मंत्री के फोन आए? क्यों मुझे रोका गया? यह अलग राजनीतिक चर्चा का विषय है।

दिवंगत अहमद के सुपुत्र फैसल ने टवीट ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता, इंतजार करके थक गया हूं

नई दिल्ली । गुजरात से आने वाले अहमद पटेल को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का करीबी और कांग्रेस का संकटमोचक समझा जाता था। लेकिन अब अहमद पटेल के निधन के बाद उनके बेटे फैसल पटेल ही कांग्रेस का संकट बढ़ाते दिख रहे हैं। इसका संकेत उन्होंने ट्वीट कर दिया है। फैसल ने ट्वीट कर लिखा, इंतजार करके थक गया हूं। हाईकमान से प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने विकल्पों को खुला रखकर चल रहा हूं। उनके ट्वीट को फैसल पटेल के अगले राजनीतिक कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां कहा जाने लगा है, कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस छोड़कर किसी और दल का हाथ थाम सकते हैं। फैसल के पिता अहमद पटेल दशकों तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा रहे और सोनिया गांधी के करीबी थे। नवंबर 2020 में अहमद का कोरोना के चलते निधन हो गया था। फैसल ने अपने ट्वीट में इसका कोई जिक्र नहीं किया है, कि वह हाईकमान से किस तरह के प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि उनके राजनीतिक बैकग्राउंड को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह राजनीति में पदार्पण कर सकते हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस की बजाय किसी और राजनीतिक दल के जरिए वह ऐसा कर सकते हैं। प्रोत्साहन न मिलने वाली बातको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वह गुजरात में अहम भूमिका की उम्मीद कांग्रेस से कर रहे थे, जो उन्हें नहीं मिल सकी। प्रोत्साहन न मिलने वाली बातको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वह गुजरात में अहम भूमिका की उम्मीद कांग्रेस से कर रहे थे, जो उन्हें नहीं मिल सकी। इससे पहले फैसल पटेल ने इसका संकेत दिया था कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भरूच से चुनाव लड़ सकते हैं। पिता के निधन के बाद फैसल पटेल ने कहा था कि मेरी रुचि इस बात में है कि कैसे अहमद पटेल की ओर से शुरू किए सामाजिक कार्यों को वह आगे बढ़ा सकें। पटेल परिवार के दो अस्पताल हैं और एक स्कूल भी है, जिसे वे संचालित करते हैं। फैसल ने कहा था, यदि हाईकमान चाहेगा, तब फिर मैं चुनाव लडूंगा। मेरी पसंद भरूच इलाका होगा, जो मेरा इलाका रहा है।% गौरतलब है कि फैसल पटेल की मुलाकात आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से भी हो चुकी है। उस मीटिंग की काफी चर्चा हुई थी। इसके बाद फैसल के ट्वीट के चलते इस बात के कयास भी लग रहे हैं कि वह भविष्य में आम आदमी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं।

कोवैक्सीन के संबंध में डब्ल्यूएचओं की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा: भारत बायोटेक

हैदराबाद । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा संयुक्त राष्ट्र की खरीद एजेंसियों के माध्यम से कोवैक्सीन की आपूर्ति निलंबित करने की घोषणा के बीच भारत बायोटेक के सूत्रों ने कहा कि दवा कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी को कोविड-19 टीके की आपूर्ति नहीं की है और निलंबन का कोई असर महसूस नहीं होगा। दवा कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अब तक कंपनी ने केंद्र सरकार के 'टीका मैत्री कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार और नौ देशों को टीकों की आपूर्ति की है, और आपातकालीन उपयोग मंजूरी (ईयूए) के तहत प्रत्यक्ष वाणिज्यिक आपूर्ति की है। कोवैक्सीन को 25 से अधिक देशों से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। कंपनी के सूत्र ने कहा, ''भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए लाइसेंस मिलने के बाद, हमने डब्ल्यूएचओ के साथ आपातकालीन उपयोग के वास्ते सूचीबद्ध (ईयूएल) किए जाने के लिए आवेदन किया और हमें वह भी मिल गया। ईयूएल का इरादा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और गावी कोवैक्स सुविधा जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को टीकों की आपूर्ति करना था। सूत्र ने कहा, ''लेकिन हमें आज तक संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी से कोई'ऑर्डर' नहीं मिला है। इसकारण हमने अभी तक कोई आपूर्ति नहीं की है। हमने केवल भारत सरकार और कुछ अन्य देशों को टीकों की आपूर्ति की है, लेकिन ये सभी आपूर्ति उन देशों से प्राप्त ईयूए पर आधारित थी।'' अंतरराष्ट्रीय टीका गठबंधन 'गावी कोवैक्स' ने भी कोवैक्सीन के लिए कोई 'ऑर्डर' नहीं दिया है। डब्ल्यूएचओ ने अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) में कमियों का हवाला देकर दो अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र की खरीद एजेंसियों के माध्यम से कोवैक्सीन की आपूर्ति को स्थगित करने की पुष्टि की थी।

संक्षिप्त समाचार

लोकसभा में सवाल पूछते हुए असहज हुई भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य

नई दिल्ली । उत्तरप्रदेश के बदायूं से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद लोकसभा में उस समय कुछ पल के लिए असहज हो गईं, जब गलती से वह गलत सवाल पूछ बैठीं। स्पीकर के टोकने पर उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ,तब संघमित्रा मौर्य ने अपना सवाल बदला। संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। लोकसभा में मंगलवार को सभापति के स्थान पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने संघमित्रा को अपना सवाल पूछने को कहा। संघमित्रा ने एक कागज लेकर खड़ी होकर उस पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक युवा कार्यक्रमों का जो प्रयोजन हुआ था उसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भागीदारी कितनी थी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में क्या था। महिलाओं की संख्या क्या थी और इन कार्यक्रमों के आयोजनों से निचले स्तर के लोगों को हुआ है क्या? इस बीच अग्रवाल ने पटल पर रखे सवाल को देखकर संघमित्रा को टोक कर कहा, संघमित्रा जी विषय बदल दिया है, आपने, सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कुछ। यह सुनकर संघमित्रा मौर्य को अपनी गलती का अहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में मौजूद उस पर्चे को बेंच पर रख दिया, जिससे वह सवाल पूछ रही थीं। संघमित्रा के पास सवाल लिखित में नहीं था। वह कुछ पल के लिए असहज हो गईं, लेकिन अपना प्रश्न याद करते हुए पूछा। संघमित्रा ने कहा, सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से पिछले सत्र में भी मांग की थी, कि सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश की घोषणा की जाए, किंतु मुझे पत्र से सूचित किया गया कि सीमित संख्या में ही राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जा सकते हैं,तब मैं सरकार से मांग करती हूं कि चैत्र मास की अष्टमी को जिस दिन सम्राट अशोक का जन्म हुआ था उस दिन को सम्राट अशोक जयंती के नाम से घोषणा की जाए ताकि जो भी लोग सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन करना चाहते है वह कर सकें, एक दिन सुनिश्चित हो सके, जिस तरह बिहार में हुआ है, पूरे देश में हो सके।

पत्रकार से बदतमीजी और धमकी मामले में अभिनेता सलमान खान को राहत, कोर्ट में पेश होने से मिली छूट

मुंबई, । पत्रकार से बदतमीजी और धमकी मामले में अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में पेश होने से छूट मिली है. मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी. दरअसल सलमान खान को 22 मार्च को अंधेरी कोर्ट ने समन भेजा था, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को पेश होना था. इस बीच सलमान खान ने मामले को खारिज करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है. मामला साल 2019 का है जब साइकिल चलाते समय पत्रकार से उनका विवाद हुआ था. आपको बता दें कि सलमान खान ने अशोक पांडे नाम के पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी जिसके बाद पांडे ने साल 2019 में सलमान खान के खिलाफ मुंबई के डीएन नगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, सलमान खान ने मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया था. घटना तब हुई जब मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया था. सलमान ने पत्रकार को धमकी दी थी. इसी मामले में अंधेरी कोर्ट ने सलमान खान को समन भेजा था और कोर्ट के सामने 5 अप्रैल को उपस्थित रहने को कहा था. सलमान खान ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस एफआईआर को ख़त्म करने के लिए निवेदन दिया है ।

शिवसेना नेता संजय राउत पर कसा क़ानूनी शिकंजा, ईडी ने सील की करोड़ों की संपत्ति

मुंबई,। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क़ानूनी शिकंजा कसते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति सील कर दी है. यह कार्रवाई मुंबई के गोरेगांव इलाके में पत्रा चाल भूमि घोटाला से संबंधित बताया गया है. बताया जा रहा है ये घोटाला 1034 करोड़ रुपये का है. जानकारी के अनुसार ईडी ने पीएमएलए जांच में राउत से जुड़े अलीबाग के आठ प्लॉट और मुंबई के दादर इलाके में स्थित एक फ्लैट कुर्क किए. बताया गया है कि संजय राउत के रिश्तेदारों की संपत्तियों को भी ईडी ने सीज किया है। ईडी ने अपनी इस कार्रवाई में 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसमें से नौ करोड़ की संपत्ति प्रवीण राउत की है जबकि दो करोड़ की संपत्ति संजय राउत की पत्नी की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1034 करोड़ के पत्रा चाल लैंड स्कैम मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीन राउत का नाम सामने आया था जिन्हें ईडी गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले की चार्जशीट भी ईडी ने दायर की है. प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा।

बिहार शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने टाली

नई दिल्ली । बिहार के शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 अप्रैल के लिए टाल दी है। बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अप्रैल को राज्य सरकार ने कानून में कई बदलाव किए हैं। कोर्ट ने संशोधित कानून रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देते हुए सुनवाई टाल दी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। जस्टिस ए एम खानविलकर और सी टी रविकुमार की बेंच याचिकाकर्ता इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइंस एसोसिएशन की याचिका को सुनते हुए यह माना था कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। इसी आधार पर बेंच ने यह आदेश दिया था कि सभी केस पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिए जाएं। आज बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी तक सभी रिकॉर्ड पटना हाई कोर्ट से यहां नहीं पहुंचे हैं। बिहार के वकील ने यह भी बताया कि 1 अप्रैल को राज्य सरकार ने कानून के कई प्रावधानों को बदला है। उन्होंने बदले हुए प्रावधानों पर हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी। जजों ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। इस बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट की 2 और बेंच बिहार के मद्यनिषेध कानून पर की जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की अपील ठुकरा दी थी।

कॅरियर गाइडेंस देश व दुनिया में आज हेल्थ सेक्टर का जितना विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे चलकर काबिल फिजियोथैरेपी की मांग और बढ़ेगी। फिजियोथैरेपी विज्ञान की ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत शारीरिक व्यायाम के जरिए व्यक्ति के रोगों व व्याधियों का उपचार किया जाता है।

फिजियोथैरेपी
वक्त की मांग

फिजियोथैरेपिस्ट का काम रोगियों में किसी बीमारी, चोट, अक्षमता या बढ़ती उम्र की वजह से उपजी शारीरिक व्याधियों का उपचार करना है। आज लोग बीमारी के उपचार के लिए समग्र नजरिया अपनाने लगे हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में फिजियोथैरेपिस्ट्स की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है।

काम का दायरा

फिजियोथैरेपिस्ट्स अस्पतालों, विकलांगों की लिए बने पुनर्वास केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए बने स्कूलों, स्वास्थ्य संगठनों के

अलावा डिफेंस मेडिकल प्रतिष्ठानों और स्पोर्ट्स क्लबों में भी अपनी सेवाएं देते है। इंजुरी व फ्रैक्चर्स, जोड़ों के दर्द, खिंचाव, मोच, स्ट्रोक्स के उपचार में काबिल फिजियोथैरेपिस्ट की सेवाएं कारगर साबित होती हैं।

बढ़ती मांग

आज जिस तरह के अत्याधुनिक अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र व क्लीनिक्स खुल रहे हैं और हेल्थ सेक्टर का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि फिजियोथैरेपिस्ट की मांग आगे चलकर और बढ़ेगा। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खुद को फिट रखने व फिटनेस संबंधी सुझाव लेने के लिए फुलटाइम पर्सनल फिजियोथैरेपिस्ट्स की सेवाएं लेते हैं। विदेशों में और खासकर अमेरिका कनाडा व आस्ट्रेलिया जैसे देशों में पर्सनल फिजियोथैरेपिस्ट्स की जबदस्त मांग है।

योग्यता

फिजियोथैरेपी में कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अस्पताल व क्लीनिक्स अमूमन ऐसे लोगों को रोजगार देते हैं, जिनके पास फिजियोथैरेपी में बैचलर डिग्री (बीपीटी) हो। बीपीटी करने के बाद छात्र यदि चाहें तो अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। फिजियोथैरेपी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि छह महीने से लेकर दो साल तक हो सकती है। डिग्री स्तर अवधि

तीन से चार साल तक होती है। प्रतिष्ठित संस्थान कॉमन टेस्ट सीईटी के जरिए बीपीटी में छात्रों की दाखिला देते है।

व्यक्तिगत योग्यता

फिजियोथैरेपिस्ट्स बनने के चाह रखने वाले अभ्यर्थियों में लंबे समय तक खड़े रहकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। काबिल फिजियोथैरेपिस्ट वहीं है जो मरीज की जरूरत को अच्छी तरह समझ सके, उसके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए। सफल फिजियोथैरेपिस्ट बनने के लिए व्यक्ति में इन खूबियों के अलावा मानवीय संरचना का सम्पूर्ण ज्ञान होना भी अति आवश्यक है।

पारिश्रमिक

इस क्षेत्र से जुड़े कोई फ्रेश ग्रेजुएट किसी हॉस्पिटल या क्लीनिक में ट्रेनी फिजियोथैरपिस्ट के तौर पर 8,000 से 12,000 रूपए वेतन पाने की उम्मीद कर सकता है। हालांकि प्रतिष्ठित अस्पतालों में आपको और भी अच्छा वेतन मिल सकता है। अनुभव हासिल करने के बाद आपके वेतन में खासा इजाफा हो सकता है। अनुभवी फिजियोथैरपिस्ट चाहे तो निजी क्लीनिक खोल कमाई कर सकते हैं।

डायटीशियन
कॅरियर का बेहतर विकल्प

आहार जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। हम जो आहार लेते है उसका शरीर में पाचन किया जाता है। प्रकृति ने विभिन्न खाद्य-पदार्थों को भोजन का रूप दिया है जिसे कच्चा या पका कर हम उपयोग करते हैं ऐसे पदार्थ हमारे पाचक अंगों द्वारा पचा लिए जाते हैं, जिनसे ऊतकों का निर्माण एवं पोषण होता है। चलने, फिरने दौडने या अन्य शारीरिक कार्य करते रहने से शरीर के भीतर के ऊतक टूटते-फूटते एवं घिसते रहते है। भोजन द्वारा हमारे शरीर की संरचना तथा मरम्मत के लिए विभिन्न पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिनसे हमें शक्ति मिलती हैऔर हमारे शीरीरिक के विभिन्न अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं ।सन्तुलित आहार और सही आहार हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है लिहाजा हमारी शारीरिक जरूरतों के अनुसार कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती हैं और कौन से खाद्य-पदार्थ से सेहत को नुकसान पंहुच सकते है, इसका जवाब डायटीशियन ही बता सकता है। जीवनशैली में आ रहे बदलावों और उसके दुष्णपरिणाम के चलते डायटीशियन एक बेहतर केरियर ऑप्शन के रूप में उभरा है। यह कोर्स अपनाकर आप अपना ही नहीं दूसरो की सेहत का भी ख्याल रख सकते है। एक डायटीशियन के रूप में आप नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग, बीमार, अभिनेताओं और खिलाडियों तक की डाइट का चार्ट बना सकते हैं। डायटीशियन लोगों को सलाह देता है, कि उसे स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए। डायटीशियन का कार्य जितना आसान दिखाई देता है वास्तव में वह उतना आसान नहीं हैं, क्योंकि रोगियों के लिए व्यक्तिगत आहार योजना बनाते हुए विभिन्न क्लीनिकल घटकों को ध्यान में रखना होता है। साथ ही रोगियों की जीवनशैली, खान-पान की आदतों पर भी विचार करना होता है ।पोरेट स्तर पर डायटीशियन की मांग बढ रही है और पांच सितारा होटलों में भी डायटीशियनों की सेवाएं ली जा रहीं हैं।

कराटे- दुश्मन को बिना किसी हथियार से हराने की तकनीक

करारे निहत्थे लडने् की एक मार्शल आर्ट है। यह एक प्रकार की कला है जिसमें हाथों तथा पैरों से वार करना तथा दुश्मन के वार को रोकना शामिल होता है। जिस व्यक्ति को करारे की तकनीक पता हो वह अपने दुश्मन को बिना किसी हथियार के हरा सकता है। एक करारे एक्सपर्ट सामने वाले को एक ही वार में चित्त भी कर सकता है। जहां जूडो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है वहीं करारे में दुश्मन पर वार भी किया जा सकता है। करारे में शारीरिक संपर्क बहुत सीमित रखा जाता है और चोट से बचने के लिए वार को नियंत्रित रखा जाता है।

करारे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है 'खाली हाथ'। करारे में शरीर की ताकत स्ट्राइकिंग प्वाइंट पर केंद्रित की जाती है। स्ट्राइकिंग प्वाइंट में हाथ, पैर का अलग भाग, एड़ी, बाजू, घुटना तथा कोहनी शामिल होते हैं। इन सभी भागों को कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस से कठोर बनाया जाता है। एक करारे एक्सपर्ट कई इंच मोटी लकड़ी को अपने हाथ या पैर से तोड़ सकता है। सही टाइमिंग, कुशलता तथा जज्बा तो इसके लिए जरूरी है ही साथ ही जरूरी होती है शारीरिक कठोरता।

करारे के खेल में वार को शरीर के संपर्क में आने से एक इंच पहले ही रोक लिया जाता है। करारे में मैच सिर्फ 3 मिनट के होते हैं। एक खेल के तौर पर इसमें कुशलता का स्तर परखने के लिए दोनों में नकली लड़ाई और औपचारिक परीक्षण दोनों का आयोजन किया जाता है। यदि प्रतियोगी अच्छे से वार न कर पाए तो जज अपना फैसला मूवमैंट्स और डिफेंस तकनीक के आधार पर सुना सकते हैं ।जजों द्वारा खिलाडियों के प्रदर्शन को वैसे ही रेटिंग दी

जाती है, जैसे जिम्नास्टिक में होता है। करारे एशिया में विकसित हुआ जिसे कई शताब्दियां लग गईं और 17वीं शताब्दी के दशक में जाकर यह कला के रूप में व्यवस्थित होने लगा। 1920 के दशक में यह जापान में बहुत प्रसिद्ध हुआ। आज पूरे विश्व में कई स्कूल करारे की ट्रेंनिंग देते हैं। 1970 में करारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल की स्थापना की गई थी।

प्राचीन चीन से शुरू और जापान में प्रसिद्ध हुआ युद्ध कौशल (मार्शल आर्ट) करारे आज पूरे विश्व में अत्यधिक लोकप्रिय है। करारे खेल भी, कला भी करारे निहत्थे लडने् की एक मार्शल आर्ट है। यह एक प्रकार की कला है जिसमें हाथों तथा पैरों से वार करना तथा दुश्मन के वार को रोकना शामिल होता है।

जिस व्यक्ति को करारे की तकनीक पता हो वह अपने दुश्मन को बिना किसी हथियार के हरा सकता है। एक करारे एक्सपर्ट सामने वाले को एक ही वार में चित्त भी कर सकता है। जहां जूडो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है वहीं करारे में दुश्मन पर वार भी किया जा सकता है। करारे में शारीरिक संपर्क बहुत सीमित रखा जाता है और चोट से बचने के लिए वार को नियंत्रित रखा जाता है। करारे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है 'खाली हाथ'। करारे में शरीर की ताकत स्ट्राइकिंग प्वाइंट पर केंद्रित की जाती है। स्ट्राइकिंग प्वाइंट में हाथ, पैर का अलग भाग, एड़ी, बाजू, घुटना तथा कोहनी शामिल होते हैं।

स्वरोजगार
कागज़ उद्योग

देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से कागज़ उद्योग देश का सबसे पुराना और अति महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग का अनुमानित आकार 25000 करोड़ रुंपये (5.95 बिलियन डॉलर) है। विश्व के कागज और कागज बोर्ड उत्पाद में इसका हिस्सा लगभग 1.6 प्रतिशत है। इस उद्योग से 1.20 लाख लागों को प्रत्यक्ष रूप से और 3.40 लाख लोगों को परेक्ष रूप से रोजगार मिला हे। अधिकतर पेपर मिल पिछले लम्बे अर्से से कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार वर्तमान समय में इनमें पुरानी से लेकर अति आधुनिक तकनीक वाली दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकियाँ इस्तेमाल हो रही हैं।

पिछले पाँच वर्षों से कागज़ की खपत लगभग 6 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है। कागज़ उद्योग को कागज के उत्पादन की किस्म के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है; जैसे क्रीमवोव, मैपलिथो, कोपलर, कोटेड पेपर, इंडिस्ट्रयल पेपर और स्पेस्लिटी पेपर। इंडिस्ट्रयल पेपर अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है, जो कि कुल खपत का लगभग 60 प्रतिशत है। अभी तक कागज उद्योग की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के बराबर रही है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें औसतन 6-7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर भारत में कागज का बाजार तेजी से बढ़ रहा है ओर यह उत्सावर्धक स्थिति को दर्शाता है। आर्थिक संवृद्धि के साथ कागज की खपत में भी अत्याधिक उछाल आने की संभावनाएँ हैं और यह 2015-16 तक 13.95 मिलियन टन तक पहुँच सकता है। भावी अनुमान यह हे कि कागज की खपत में सकल घरेलू उत्पाद के गुणांकों में वृद्धि होगी और इस प्रकार प्रति व्यक्ति 1 किलाग्राम खपत की वृद्धि से उसकी मांग में 1 मिलियन टन की वृद्धि होगी। उद्योग के अनुमानानुसार वर्ष 2012-13 तक कागज़ उत्पादन 8.4 प्रतिशत संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर) से बढ़ा है, जबकि कागज की खपत 9 प्रतिशत संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर) से बढ़ी है। कम खर्च व लागत में कागज उद्योग स्वरोजगार का बेहतर जरिया बन सकता है।

पैरा-मैडीकल कोर्सेज
में संवारें कॅरिअर

यदि आपकी बारहवीं परीक्षा की श्रेणी या अंक बहुत अच्छे नहीं हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह यह है कि पैरा-मैडीकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए सी.पी.एम.टी. जैसी कठिन प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती। डॉक्टर जब मरीज को देख लेता है उसके बाद (कुछ मामलों में डाक्टर से पहले भी) सारा काम पैरा-मैडीकल के लोग ही संभालते हैं।

मरीज के खून, पेशाब, बलगम, वीर्य, टिश्यू आदि की जांच करनी हो, उसका एक्स-रे, ई.सी.जी., ई.ई.जी., एम.आर.आई., अल्ट्रा साऊंड, सी.टी. स्कैन, टी.एम.टी.,पी.एफ.टी., मैमोग्राफी आदि इंजैक्शन व दवा देनी हो तथा इसके अलावा भी अनेक ऐसे काम हैं जिसे पैरा-मैडीकल स्टाफ ही करता है। आप्रेशन करते समय एक डाक्टर को असिस्ट करने के लिए पैरा-मैडीकल स्टाफ होता है। मैडीकल फील्ड का लगभग सारा टैक्निकल स्टाफ पैरा-मैडीकल के अंतर्गत ही आता है।

इसके तहत प्रमुख कोर्स व संबंधित कार्य इस प्रकार हैं- मैडीकल लैब टैक्नोलॉजी , एक्स-रे टैक्नोलॉजी एंड रेडियोलॉजी/रेडियोग्राफी, ऑप्टोमीट्री या ऑप्थाल्मिक टैक्नोलॉजी, प्रॉस्थैटिक एवं ऑथोटिक इंजीनियरिंग, फिजियोथैरिपी एंड ऑकुपेशनल थैरेपी, डैंटिस्ट असिस्टैंट, स्पीच थैरेपी एंड ऑडियोलॉजी, क्लीनिकल चाइल्ड डिवैल्पमैंट, रिहैबिलिटेशन, मैडीकल ट्रांसक्रिप्शन, कम्युनिटी हैल्थ वर्कर्स कोर्स (मेल/फीमेल/मल्टीपर्पज़) ऑप्रेशनल थैरेपिस्ट असिस्टैंट/ ऑप्रेशन थिएटर असिस्टैंट व टैक्नीशियन कोर्स, कॉर्डियोलॉजी टैक्नीशियन कोर्स, सी.टी. स्कैन टैक्नीशियन कोर्स।

इनके साथ ही फॉर्मेसी, नर्सिंग एवं मिडवाइफरी तथा साइकोलॉजी की गणना भी पैरा-मैडीकल के अंतर्गत ही की जाती है। उपरोक्त सभी कोर्सों में सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, बी.एससी., एम.एससी., बैचलर या मास्टर डिग्री विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रदान की जाती है।

संस्थान

- पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सैक्टर-11,चंडीगढ़-1600012
- पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज, रोहतक-124001, हरियाणा।
- गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110007

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मैं 'भारत विरोधी' या 'अमेरिका विरोधी' नहीं हूं: इमरान खान

इस्लामाबाद ।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि वह ''भारत विरोधी या अमेरिका विरोधी'' या किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं हैं, वह सभी देशों के साथ आपसी सम्मान पर आधारित अच्छे संबंध चाहते हैं। पीएम इमरान खान ने कहा कि नेशनल असेंबली भंग होने के बाद चुनाव की तैयारी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की ओर देखने की संयुक्त विपक्ष की रणनीति इसका संकेत है, कि वह ''जनता की प्रतिक्रिया से डरता है।'' किसी कथित विदेशी पत्र को लेकर विवाद से जुड़े सवाल के जवाब में खान ने कहा कि वह किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं हैं। खान के हवाले से कहा, मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं।

मैं भारत विरोधी या अमेरिका विरोधी नहीं हूं, लेकिन हम नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं। मैं उनसे दोस्ती चाहता हूं और सम्मान की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह उन देशों के खिलाफ हैं, जो अन्य संप्रभु देशों का अनादर करते हैं और केवल आदेश जारी करते हैं। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने प्रधानमंत्री खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने खान की सिफारिश पर निचले सदन को भंग कर दिया था। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के मामले में सुनवाई सोमवार को एक दिन के लिए स्थगित कर दी। न्यायालय ने इस हाई प्रोफाइल मामले में ''उचित आदेश'' देने की बात कही।

चुनाव में निजी समूहों से चंदा लेने पर रोक लगाने वाले अमेरिकी प्रांतों में शामिल हुआ मिसिसिप्पी

जैक्सन ।

अमेरिका में मिसिसिप्पी अब रिपब्लिकन पार्टी के शासन वाले उन प्रांतों में शामिल हो गया है, जहां चुनावी अभियान के लिए निजी समूहों से चंदा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग द्वारा कथित तौर पर चंदा दिए जाने के संदेह के मद्देनजर उठाया गया है। मिसिसिप्पी के गवर्नर टेट रीव्स ने 'हाउस बिल 1365' पर दस्तखत किए, जो एक जुलाई से कानूनी रूप से प्रभावी हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि चुनाव संपन्न कराने वाले प्रांतीय या स्थानीय अधिकारी मतदाताओं को जागरूक करने, उन तक पहुंच बनाने या मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम के लिए किसी भी निजी समूह से न तो चंदा मांग सकेंगे और न ही उसे स्वीकार कर सकेंगे। फेसबुक पर जारी एक वीडियो में रीव्स ने कहा कि वह 2020 के चुनाव को प्रभावित करने की एक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी की कोशिशों को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने आरोप लगाया चाहे यह कंजरवेटिव नेताओं की आवाज दबाने या फिर उन सूचनाओं के प्रवाह को रोकने की कोशिश थी, जिनसे वे सहमत नहीं हैं,

कैलिफोर्निया के प्रौद्योगिकी जगत के दिग्गज अमेरिकी अवाम पर अपनी विचारधारा थोपने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। रीव्स ने कहा हमारे चुनाव मार्क जुकरबर्ग जैसे अरबपतियों पर निर्भर नहीं होने चाहिए, खासतौर पर तब जब फेसबुक सरीखी कंपनियां अपने मंच पर कंजरवेटिव आवाजों को व्यवस्थित रूप से दबाने की कोशिशों में जुटी हों।

बुका में रूसी सैनिकों के हटने के बाद सड़कों पर शव पड़े मिले

बुका ।

रूस को वैश्विक स्तर पर निंदा और युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना करना पड़ा जब कीव के बाहरी इलाके से रूसी सैनिकों के हटने के बाद वहां सड़कों पर शव पड़े मिले। ये शव आम नागरिकों के प्रतीत होते हैं और इनमें से कुछ को जानबूझकर करीब से गोली मारी गई। खुले में पड़े शव या जल्दबाजी में खोदी गई कब्रों में शवों की तस्वीरें सामने आने के बाद रुस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की मांग की गई। इसमें रूस से ईंधन आयात में कटौती की मांग भी शामिल है। इस बीच, जर्मनी ने 40 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर लिथुआनिया ने रूसी राजदूत को बाहर कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कीव से बाहर निकले ताकि वह बुका नगर की 'भयावहता को खुद की आंखों से देख सकें' जिसे उन्होंने ''नरसंहार'' एवं ''युद्ध अपराध'' करार दिया। जेलेंस्की ने कहा, मृत लोगों के शव बेसमेंट आदि में मिले हैं और यह बात सामने आई कि उनका गला घोंटा गया और प्रताड़ित किया गया।'' यूरोपीय नेताओं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने रक्तपात की निंदा की। इनमें से कुछ ने नरसंहार भी कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधों के मुकदमे का सामना करना चाहिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कीव के बाहर के दृश्यों को मंच-प्रबंधित रूस विरोधी उकसावे के रूप में वर्णित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते रूसी सैनिकों के जाने के एक दिन बाद बुका के महापौर ने अत्याचारों का कोई जिक्र नहीं किया,।

यूएनएससी में रूस अपने 'वीटो' का इस्तेमाल करता रहेगा : अमेरिका

वाशिंगटन ।

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित मुद्दों पर रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अपने 'वीटो' का इस्तेमाल करना आगे भी जारी रखेगा। सुलिवन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा चूंकि, रूस यूएनएससी का स्थाई सदस्य है, इसलिए यह कल्पना करना कठिन होगा कि वह किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूक्रेन में अत्याचारों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की कोशिश के दौरान यूएनएससी के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा जहां तक जवाबदेह ठहराने का सवाल है, अतीत में भी इसके रचनात्मक समाधान निकाले गए हैं। हालांकि, मैं यह अनुमान नहीं लगाने जा रहा हूं कि यहां कौन-सा समाधान काम करेगा या कौन-सा मंच इस मुद्दे को उठाने के लिए सही है। सुलिवन ने जोर दिया कि इन युद्ध अपराधों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए अपराधों के लिए उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अमेरिका दुनिया के साथ मिलकर काम करेगा।

उन्होंने कहा हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों को अंजाम दिया है और बुशा में सामने आया मंजर उसी का सबूत है। जैसा कि राष्ट्रपति (जो बाइडन) ने कहा है, हम इन अपराधों की पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी प्रशासन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर उस पर और प्रतिबंधों लगाने को लेकर भी काम कर रहा है।

पेंटागन बोला- पिछले एक दशक में भारत ने अपने रक्षा उपकरण में जो विविधता लाई उसे लेकर हम उत्साहित

वॉशिंगटन । भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन ने कहा है कि भारत द्वारा सैन्य और रक्षा उपकरणों की खरीद में विविधता लाने से उनका देश उत्साहित है। इसके साथ ही पेंटागन ने नई दिल्ली के रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के निर्णय पर चिंता जताई। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया, इस खरीद पर हमारे भारतीय साझेदारों के साथ हमारा स्पष्ट रवैया है। हम आग्रह करते हैं कि अन्य देश रूस के उपकरण न खरीदें। किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा, पिछले एक दशक में भारत ने अपने रक्षा उपकरण में जैसी विविधता लाई है उसे लेकर हम उत्साहित हैं। इसलिए हम भारत की जरूरतों के हिसाब से बातचीत जारी रखेंगे। भारत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा 'खास तौर पर इस खरीद को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में हमने भारत के साफ तौर पर बता दिया है।' अक्टूबर 2018 में भारत ने एस-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए रूस के साथ पांच अरब डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

चीन में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटों में सामने आए 16 412 नए मरीज, सेना ने संभाला मोर्चा

बीजिंग ।

चीन में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। देश में कोविड-19 के 16 हजार 412 नए मरीज मिले हैं। खबर है कि साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन कई शहरों और खासतौर से शंघाई के हाल ज्यादा खराब हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पहले ही कई देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। चीन के 27 से ज्यादा प्रांतों और शहरों में कोविड के नए मरीज मिल रहे हैं। इनमें से अधिकांश कोरोना के तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। इसके चलते अधिकारियों को क्षेत्रों में कड़ी पाबंदियां लागू करनी पड़ रही हैं। वहीं, कोरोना के खिलाफ जंग में देश की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शंघाई में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। यहां 2 करोड़ से ज्यादा रहवासियों की कोविड जांच के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। शहर में 28 मार्च को दो चरणों के लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। फिलहाल, अधिकारियों ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि ये पाबंदियां कब हटेंगी। इसके अलावा यहां बगैर लक्षणों वाले मरीज भी चिंता का कारण बने हुए हैं। सोमवार को शहर में 8 हजार 581 एसिम्प्टोमैटिक मामले सामने आए। जबकि, सिम्प्टोमैटिक मामलों की संख्या 425 थी। इधर, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने सेना, नौसेना और लॉजिस्टिक सपोर्ट से 2000 हजार से ज्यादा कर्मियों को रवाना किया है। शहर में पहले ही 38 हजार स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि वुहान के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह चीन की सबसे बड़ी कवायद है। साल 2019 में वुहान में पहली बार नोवल कोरोना वायरस मिला था। खबर है कि कोविड मरीज से मिले सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबटाइप मिला है। हालांकि, नया आइट्रेशन ओमिक्रॉन की बीए.1.1 ब्रांच से विकसित हुआ है।

संक्षिप्त समाचार

रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने 'वीटो' का इस्तेमाल करना आगे भी जारी रखेगा

वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित मुद्दों पर रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अपने 'वीटो' का इस्तेमाल करना आगे भी जारी रखेगा। सुलिवन ने कहा, चूंकि, रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, इसकारण यह कल्पना करना कठिन होगा कि वह किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूक्रेन में अत्याचारों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की कोशिश के दौरान यूएनएससी के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ''जहां तक जवाबदेह ठहराने का सवाल है, अतीत में भी इसके रचनात्मक समाधान निकाले गए हैं। हालांकि, मैं यह अनुमान नहीं लगाने जा रहा हूं कि यहां कौन-सा समाधान काम करेगा या कौन-सा मंच इस मुद्दे को उठाने के लिए सही है।'' सुलिवन ने जोर दिया कि इन युद्ध अपराधों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि यूक्रेन में रूस द्वारा किए गए अपराधों के लिए उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अमेरिका दुनिया के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा, ''हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों को अंजाम दिया है और बुशा में सामने आया मंजर उसी का सबूत है। जैसा कि राष्ट्रपति (जो बाइडन) ने कहा है, हम इन अपराधों की पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के साथ मिलकर काम करेंगे।'' अमेरिकी प्रशासन पुतिन और रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर उस पर और प्रतिबंधों लगाने को लेकर भी काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन एक 'युद्ध अपराधी' हैं।

अमेरिका मानवाधिकार निकाय से रूस का निलंबन चाहता

बुखारेस्ट । संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय से रूस का निलंबन चाहता है, क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं। थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कीव के पास बुका शहर में आम लोगों के खिलाफ हिंसा के बारे में सप्ताहांत आई खबर के मद्देनजर मानवाधिकार परिषद में रूस से उसकी सीट छीनने का आह्वान किया। आम लोगों के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आने के बाद रूस के प्रति काफी आक्रोश काफी बढ़ा हैं, उसकी निंदा की जा रही है। थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा, हम मानते हैं कि रूसी सेना के सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किया है और हम मानते हैं कि रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।'' यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि कीव के आसपास के शहरों में आम लोगों के 410 शव मिले हैं जिन्हें हाल के दिनों में रूसी सेना से फिर से हासिल किया गया है। अमेरिकी अधिकारी ने मानवाधिकार परिषद में रूस की भागीदारी को एक ''ढोंग'' करार दिया और कहा कि यह निकाय की विश्वसनीयता को आहत करता है। रूस को निलंबित करने के किसी भी निर्णय के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय की आवश्यकता होगी।

मॉस्को आने की सजा भुगत रहे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान - रुस

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच रूस की भी एंट्री हो चुकी है। रूस ने इमरान के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। रूस ने कहा है कि अमेरिका इमरान को मास्को दौरा करने की सजा दे रहा है। रअसल पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिराने की %विदेशी साजिश में शामिल थे। इस लेकर रूस ने बयान दिया है। रूस ने कहा है कि पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में अमेरिका ने ÷बेशर्मी से हस्तक्षेप करने का प्रयास÷ किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने ÷अवज्ञाकारी÷ इमरान खान को दंडित करने की मांग की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस को पता चला है कि राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री की सलाह पर 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। उन्होंने कहा, इस साल 23-24 फरवरी को इमरान की मास्को की कामकाजी यात्रा की घोषणा के तुरंत बाद, अमेरिकियों और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने प्रधानमंत्री पर कठोर दबाव डालना शुरू कर दिया था, यात्रा को रद्द करने के लिए एक अल्टीमेटम दिया भी दिया था।÷ रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, इसके बावजूद वे हमारे यहां आए, तब [लू] ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर मांग की कि यात्रा तुरंत बाधित हो। उनकी (लू) मांग को भी खारिज कर दिया गया।÷जखारोवा ने कहा, पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक इसी साल 7 मार्च को पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद के साथ बातचीत में, की घटनाओं पर पाकिस्तानी नेतृत्व की संतुलित प्रतिक्रिया की तीखी निंदा की और स्पष्ट किया ।

श्रीलंका के विपक्ष नेता की पीएम मोदी से अपील, हमें इस संकट से बच लीजिए

कोलंबो ।

इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा श्रीलंका मदद के लिए भारत के सामने हाथ फैला रहा है। बता दें कि, श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह करते हुए कहा कि, देश के इस संकट के समय में भारत श्रीलंका का साथ दें। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा ने पीएम मोदी से आग्रह करते हुए कहा कि, कृपया कोशिश करें और श्रीलंका की यथासंभव मदद करें। यह हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को बचाने की जरूरत है प्रेमदासा ने विश्वसनीय माध्यम के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश पहुंचाया है। बता दें कि, प्रेमदासा ने श्रीलंका के 26 मंत्रियों द्वारा दिए इस्तीफे को ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि, मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद और हम सभी तब से तैयार हैं जब से हमने समाज सेवा और राजनीतिक सेवा में प्रवेश किया है। हम किसी भी घटना के लिए तैयार हैं । उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए यह ड्रामा किया जा रहा है। ये लोगों को राहत देने की दिशा में कोई वास्तविक प्रयास नहीं है। ये बस उन्हें बेवकूफ बनाने की कवायद है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजित निवर्ड कैबराल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने ट्वीट किया कि सभी कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफा देने के संदर्भ में मैंने मंगलवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को गवर्नर, सेंट्रल बैंक के ऑफ श्रीलंका के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसी बीच श्रीलंका के विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुजारिश की है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश को इस राष्ट्रीय संकट से निकालने के लिए समाधान ढूढ़ने के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों को मंत्रालय में शामिल होने के लिए कहा है और एक सामूहिक सरकार बनाने की अपील की है। भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में लोगों के गुस्से को शांत करने की सरकार की कोशिशों के बीच नए मंत्रिमंडल को जल्द ही शपथ दिलाई जा सकती है। बता दें कि, श्रीलंका इनदिनों अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात इतने खराब है कि, अब स्ट्रीट लाइन जलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मंहगाई आसमान की छलांग लगाई है और इसके बाद में लोगों के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया है। लोगों में सरकार को लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा है ।

इमरान की विदेशी साजिश वाली थ्योरी पर सेना को भी भरोसा नहीं, सबूतों को नहीं माना पुख्ता

इस्लामाबाद । पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार भंग हो चुकी है। हालांकि, इमरान खान विदेशी साजिश होने की बात कहकर अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने में सफल रहे, लेकिन उनके इस दावे पर विपक्ष के साथ-साथ अब सेना ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की सेना को इमरान की विदेशी साजिश वाली थ्योरी पर भरोसा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 27 मार्च को हुई राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक में सैन्य नेतृत्व ने इमरान खान के दावों के विपरीत कहा कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह साबित कर सके कि पीटीआई सरकार को हटाने की साजिश में अमेरिका शामिल था। 27 मार्च को, प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी (एनएससी) ने राजनयिक केबल पर चर्चा के लिए बैठक की थी। इस बैठक में पीटीआई सरकार ने दावा किया था कि उनके पास सबूत है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका ने साजिश रची है। बैठक के बाद एनएससी ने बयान जारी कर इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यह पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है। इसके बाद एनएससी ने अमेरिका को डेमार्श जारी करने का फैसला किया है। दरअसल, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जब विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी और माना जा रहा था कि इमरान सरकार गिर जाएगी, तब इमरान सरकार की तरफ से सदन को बताया गया कि सरकार गिराने की विदेशी साजिशें हो रही हैं। इस आधार पर ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला किया।

भारतीय मूल के कैंसर सर्जन डॉ पी रघु राम को ब्रिटेन का दूसरा सर्वोच्च सम्मान

लंदन।

हैदराबाद के डॉ पी रघु राम को ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े सम्मान मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हासिल हुआ। पिछले 100 सालों में ब्रिटेन साम्राज्य के इस सर्वोच्च सम्मान को हासिल करने वाले वह पहले भारतीय मूल के सबसे युवा सर्जन है। महारानी एलिजाबेथ की तरफ से प्रिंस चार्ल्स, वेल्स के राजकुमार ने डॉ पी रघु राम को लंदन के विंडसर महल में यह सम्मान प्रदान किया। नाइटहुड-डेमेहुड के बाद ब्रिटेन साम्राज्य का यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉ रघु राम स्तन संबंधी बीमारियों के लिये बनाए गये किम्स-उषालक्ष्मी केंद्र के निदेशक और ऊषा लक्ष्मी स्तन कैंसर फाउंडेशन के संस्थापक सीईओ हैं। उन्हें यह सम्मान स्तन कैंसर के उपचार में सुधार को लेकर किए गए उल्लेखनीय कार्य सर्जरी से जुड़ी शिक्षा को लेकर भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दिया गया। डॉक्टर ने अपने इस सम्मान को अपने परिवार, मरीजों और किम्स को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने खुद को इस सम्मान से नवाजने के लिए महारानी को भी शुक्रिया अदा किया। यही नहीं डॉ रघु राम 2015 में पदमश्री और 2016 में डॉ बीसी रॉय राष्ट्रीय अवार्ड हासिल करने वाले भी सबसे युवा डॉक्टर में से एक हैं। उन्होंने दक्षिण एशिया का पहला व्यापक स्तन कैंसर से जुडे केंद्र की स्थापना की है। जिससे इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरुकता फैल सके। यही नहीं दी असोसियेशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन ऑफ इंडिया के गठन में भी उनका अहम योगदान है। यह वह मंच है, जहां पर स्तन सर्जरी की कला और विज्ञान को जानने वाले सर्जन एक साथ होते हैं। डॉ पी रघु राम से पहले ओबीई सम्मान हासिल करने वालों में अभिनेता ओम पुरी, फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम और उनकी पत्नी विक्टोरिया बेकहम, क्रिकेटर बेन स्टोक्स, लेखक जेके राउलिंग और अभिनेत्री कियारा नाइटली शामिल हैं।

गुजरात चुनाव में बहुमत नहीं तो आप को 50 से अधिक सीटें जरूर मिलेंगी : संदीप पाठक

अहमदाबाद ।

पंजाब में शानदार सफलता से गदगद आम आदमी पार्टी (आप) को गुजरात विधानसभा के चुनाव में अपने लिए अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं7 आप का दावा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत नहीं तो 50 अधिक सीटों पर जीत जरूर मिलेगी7 गुजरात आप के प्रभारी संदीप पाठक का दावा है कि अगर राज्य में अभी चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी 58 सीटें जीत सकती है7 एक एजंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में आप 55 सीटें जीत सकती है7 जबकि हमारे आंतरिक सर्वे में आम आदमी पार्टी को 58 सीटें मिलने की संभावना है7 संदीप पाठक ने कहा कि गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस मौजूदा समय में भाजपा को हरा नहीं सकती7 इसलिए गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को एक अच्छा विकल्प मानते हैं7 उन्होंने कहा कि हम यहां किसी पार्टी को हराना नहीं चाहते बल्कि यह चाहते हैं कि गुजरात के लोगों की जीत हो7 गुजरात के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। पाठक ने कहा कि एक समय था जब गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं7 आप की नजर उन इलाकों पर है जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भाजपा पर भरोसा नहीं करते। हम ऐसे लोगों के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप पाठक ने कहा कि वैसे गुजरात विधानसभा के चुनाव दिसंबर तक होंगे, परंतु कुछ जानकारों के मुताबिक राज्य में चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। गौरतलब है पंजाब की जीत के रणनीतिकार माने जाते संदीप पाठक दिल्ली आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। गौरतलब है पंजाब की जीत के रणनीतिकार माने जाते संदीप पाठक दिल्ली आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आप को मिली एकतरफा जीत का श्रेय संदीप पाठक की रणनीति को दिया जाता है। संदीप पाठक अब पंजाब की रणनीति पर गुजरात में करना चाहते हैं। संदीप पाठक का कहना है कि जो लोग अच्छी स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं गुजरात में चाहते हैं, उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। उनका यह भी कहना है कि गुजरात और पंजाब में काफी समानता है और दोनों ही राज्य तरक्कीपसंद हैं तथा दोनों को बदलाव की जरूरत है।

संक्षिप्त समाचार

लोकसभा में सवाल पूछते हुए असहज हुई भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य

नई दिल्ली । उत्तरप्रदेश के बदायूं से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद लोकसभा में उस समय कुछ पल के लिए असहज हो गईं, जब गलती से वह गलत सवाल पूछ बैठीं। स्पीकर के टोकने पर उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ,तब संघमित्रा मौर्य ने अपना सवाल बदला। संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। लोकसभा में मंगलवार को सभापति के स्थान पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने संघमित्रा को अपना सवाल पूछने को कहा। संघमित्रा ने एक कागज लेकर खड़ी होकर उस पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक युवा कार्यक्रमों का जो प्रयोजन हुआ था उसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भागीदारी कितनी थी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में क्या था। महिलाओं की संख्या क्या थी और इन कार्यक्रमों के आयोजनों से निचले स्तर के लोगों को हुआ है क्या? इस बीच अग्रवाल ने पटल पर रखे सवाल को देखकर संघमित्रा को टोक कर कहा, संघमित्रा जी विषय बदल दिया है, आपने, सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कुछ। यह सुनकर संघमित्रा मौर्य को अपनी गलती का अहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में मौजूद उस पर्चे को बेंच पर रख दिया, जिससे वह सवाल पूछ रही थीं। संघमित्रा के पास सवाल लिखित में नहीं था। वह कुछ पल के लिए असहज हो गईं, लेकिन अपना प्रश्न याद करते हुए पूछा। संघमित्रा ने कहा, सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से पिछले सत्र में भी मांग की थी, कि सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश की घोषणा की जाए, किंतु मुझे पत्र से सूचित किया गया कि सीमित संख्या में ही राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जा सकते हैं,तब मैं सरकार से मांग करती हूं कि चैत्र मास की अष्टमी को जिस दिन सम्राट अशोक का जन्म हुआ था उस दिन को सम्राट अशोक जयंती के नाम से घोषणा की जाए ताकि जो भी लोग सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन करना चाहते है वह कर सकें, एक दिन सुनिश्चित हो सके, जिस तरह बिहार में हुआ है, पूरे देश में हो सके।

पत्रकार से बदतमीजी और धमकी मामले में अभिनेता सलमान खान को राहत, कोर्ट में पेश होने से मिली छूट

मुंबई, । पत्रकार से बदतमीजी और धमकी मामले में अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में पेश होने से छूट मिली है. मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी. दरअसल सलमान खान को 22 मार्च को अंधेरी कोर्ट ने समन भेजा था, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को पेश होना था. इस बीच सलमान खान ने मामले को खारिज करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है. मामला साल 2019 का है जब साइकिल चलाते समय पत्रकार से उनका विवाद हुआ था. आपको बता दें कि सलमान खान ने अशोक पांडे नाम के पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी जिसके बाद पांडे ने साल 2019 में सलमान खान के खिलाफ मुंबई के डीएन नगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, सलमान खान ने मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया था. घटना तब हुई जब मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया था. सलमान ने पत्रकार को धमकी दी थी. इसी मामले में अंधेरी कोर्ट ने सलमान खान को समन भेजा था और कोर्ट के सामने 5 अप्रैल को उपस्थित रहने को कहा था. सलमान खान ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस एफआईआर को ख़त्म करने के लिए निवेदन दिया है ।

शिवसेना नेता संजय राउत पर कसा क़ानूनी शिकंजा, ईडी ने सील की करोड़ों की संपत्ति

मुंबई,। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क़ानूनी शिकंजा कसते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति सील कर दी है. यह कार्रवाई मुंबई के गोरेगांव इलाके में पत्रा चाल भूमि घोटाला से संबंधित बताया गया है. बताया जा रहा है ये घोटाला 1034 करोड़ रुपये का है. जानकारी के अनुसार ईडी ने पीएमएलए जांच में राउत से जुड़े अलीबाग के आठ प्लॉट और मुंबई के दादर इलाके में स्थित एक फ्लैट कुर्क किए. बताया गया है कि संजय राउत के रिश्तेदारों की संपत्तियों को भी ईडी ने सीज किया है। ईडी ने अपनी इस कार्रवाई में 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसमें से नौ करोड़ की संपत्ति प्रवीण राउत की है जबकि दो करोड़ की संपत्ति संजय राउत की पत्नी की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1034 करोड़ के पत्रा चाल लैंड स्कैम मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीन राउत का नाम सामने आया था जिन्हें ईडी गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले की चार्जशीट भी ईडी ने दायर की है. प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा।

बिहार शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने टाली

नई दिल्ली । बिहार के शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 अप्रैल के लिए टाल दी है। बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अप्रैल को राज्य सरकार ने कानून में कई बदलाव किए हैं। कोर्ट ने संशोधित कानून रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देते हुए सुनवाई टाल दी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। जस्टिस ए एम खानविलकर और सी टी रविकुमार की बेंच याचिकाकर्ता इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइंस एसोसिएशन की याचिका को सुनते हुए यह माना था कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। इसी आधार पर बेंच ने यह आदेश दिया था कि सभी केस पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिए जाएं। आज बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी तक सभी रिकॉर्ड पटना हाई कोर्ट से यहां नहीं पहुंचे हैं। बिहार के वकील ने यह भी बताया कि 1 अप्रैल को राज्य सरकार ने कानून के कई प्रावधानों को बदला है। उन्होंने बदले हुए प्रावधानों पर हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी। जजों ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। इस बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट की 2 और बेंच बिहार के मद्यनिषेध कानून पर की जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की अपील ठुकरा दी थी।

भगवा रंग की टोपी और पीएम की फोटो वाली चाकलेट के साथ दिखे भाजपा सांसद

नई दिल्ली ।

भाजपा की मंगलवार सुबह संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक में भाजपा के तमाम सांसद मौजूद रहे। बैठक के दौरान अलग नजारा देखने को मिला। पार्टी के कई सांसदों ने भगवा रंग की टोपी पहनी हुई थी। बताया जा रहा है कि ये वहां ही टोपी है, इस पीएम नरेन्द्र मोदी ने बीते महीने अहमदाबाद रोड शो में पहना था। खबर के मुताबिक, भाजपा सांसदों को चाकलेट भी दी गई। चाकलेट के रैपर पर पीएम मोदी की तस्वीर छपी थी। बताया जा रहा है कि इस टोपी को गुजरात भाजपा इकाई ने तैयार करवाया है। टोपियों को संसदीय दल की बैठक में आए भाजपा सांसदों में बांटा गया था। टोपी पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का निशान था। इसके अलावा सांसदों को चाकलेट भी दी गई। टोपी का डिजाइन उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी से लिया है। उत्तराखंड की टोपी पर ब्रह्मकमल अंकित होता है। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राजकीय फूल है। मोदी ने उत्तराखंडी टोपी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पहना था। इसके बाद से टोपी की डिमांड काफी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने बैठक में 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पर चर्चा की। भाजपा ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन से होगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने नौ दिनों के लिए तय कार्यक्रम पर भाजपा सांसदों से चर्चा की। भाजपा के एक सांसद ने कहा कि पीएम ने पोषण अभियान जैसे कई सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी बात की। उन्होंने हम सभी से पोषण अभियान और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार करने के लिए कहा गया है।

कर्नाटक सरकार में बदलाव के आसार

नई दिल्ली । कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले ही प्रदेश भाजपा में गतिविधियां तेज हो गई हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कैबिनेट में बदलाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। वह राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। राज्य में अप्रैल 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं, इस सियासी उठा पटक के बीच राज्य के कई भाजपा नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा डाल लिया है। बोम्मई ने कहा, मैंने नड्डा जी और अमित शाह जी से मुलाकात के लिए समय मांगा है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलना अभी बाकी है। अगर समय मिलेगा तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। भाजपा सूत्रों के हवाले से लिखा कि कैबिनेट में जगह पाने की संभावनाएं और बाहर होने का डर लेकर कई मंत्री और नेता भी दिल्ली पहुंच गए हैं। हाल के हफ्तों में बोम्मई ने कहा कि वह अप्रैल की शुरुआत में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान कैबिनेट विस्तार पर अंतिम फैसला ले लेंगे। खास बात है कि वे दिल्ली भी ऐसे समय पर पहुंच रहे हैं, जब भाजपा संसदीय दल की बैठक हो रही है। फिलहाल, कर्नाटक 34 मंत्रियों वाली कर्नाटक सरकार में चार पद रिक्त हैं। अटकलें हैं कि पार्टी नए चेहरों को शामिल करने के लिए कम से कम चार मंत्रियों को बाहर कर सकती है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि भाजपा 2023 चुनाव से पहले नए पार्टी अध्यक्ष नए पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर रही है। बोम्मई ने कहा, मुझे कैबिनेट विस्तार के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार मैं दिल्ली जाऊंगा और नड्डा जी और अमित जी से मिल लूंगा, तो संभावना है कि कुछ स्थिति साफ हो जाए।

कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति से वंचित न रह जाएं। कोर्ट इस तरह के बच्चों की स्थिति पर खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट बच्चों की शिक्षा जारी रखने और उनकी दूसरी जरूरतों का ध्यान रखने का राज्यों को निर्देश दे चुका है। मामले में एमिकस क्यूरी की हैसियत से कोर्ट की सहायता कर रहे वकील गौरव अग्रवाल ने आशंका जताई थी कि माता-पिता पर बकाया कर्ज़ की वसूली के लिए वित्तीय संस्थान संपत्ति पर कब्ज़ा कर सकते हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्यों को इस पहलू पर गौर करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार से संरक्षण आयोग की तरफ से रखी गई रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। बताया है देशभर में कोरोना के चलते 10,793 बच्चों ने दोनों अभिभावकों को खोया है। 1,51,322 बच्चों के माता-पिता में से एक की मृत्यु इस बीमारी से हुई है। आयोग ने यह भी बताया है कि राज्यों ने इन बच्चों की स्थिति जानने के लिए सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अब तक पूरी नहीं की है। कोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए राज्यों को प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कहा।

तब्लीगी जमात के मामले में दिल्ली पुलिस के पास जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका

नई दिल्ली ।

कोरोना महामारी के दौरान विदेश से निजामुद्दीन मरकज में आए तब्लीगी जमात के सदस्यों को अपने घर में शरण देने के मामले में दर्ज एफआइआर मामले में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आखिरी मौका दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने अदालत के आदेश के बावजूद भी लिखित जवाब नहीं दाखिल करने पर सवाल उठाया। साथ ही पुलिस को आखिरी मौका देते हुए सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता अशिमा मंडला ने पीठ को बताया कि पुलिस ने अदालत के निर्देश के बावजूद भी लिखित बयान नहीं दिया है। पिछली सुनवाई पर पीठ ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या गत वर्ष तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वैध वीजा पर आए विदेशियों को भारतीय नागरिकों द्वारा अपने घर में शरण देने पर कोई प्रतिबंध लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने देशव्यापी लाकडाउन के दौरान जमातियों को अपने घर में पनाह देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी रद करने की मांग करते हुए कहा है कि लाकडाउन के कारण यात्रा नहीं करने वालों को उन्होंने शरण दी थी। पुलिस ने गलत तरीके से यह मामला दर्ज किया है। लुटियंस दिल्ली इलाके से वाहन चोरी करने वाले एक बदमाश को नई दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। आरोपित की पहचान अजय उर्फ आदेश के तौर पर हुई है। उसके कब्जे से चोरी की स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। आरोपित पर पहले से चार मामले दर्ज हैं। डीसीपी अमृता गुगुलोथ के मुताबिक तुगलक लेन स्थित जेजे कैंप निवासी चंदन शाह ने तुगलक रोड थाने में अपनी स्विफ्ट डिजायर कार चोरी होने की शिकायत दी थी। जांच टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर एक संदिग्ध की पहचान की।

पाकिस्तान और श्रीलंका की जगह नेपाल नहीं फंसा ड्रैगन के जाल में

नई दिल्ली ।

नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा पिछले सप्ताह भारत आए थे,तब उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में बताया था कि कैसे उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कह दिया कि हमें लोन की नहीं अनुदान की जरूरत है। देउबा ने कहा था कि हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए चीन से कर्ज की जरूरत नहीं है। तथ्य यह है कि चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत नेपाल ने कोई भी करार नहीं किया और काठमांडू से वांग यी खाली हाथ ही लौट आए। नेपाल के फैसले को दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुकाबले समझदारी भरा ही कहा जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में आज जो अस्थिरता और आर्थिक संकट के हालात हैं। उसकी एक वजह चीन को भी माना जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जो कुल कर्ज है, उसमें 10 फीसदी हिस्सा चीन का ही है। आज इमरान खान चीन के बेहद करीबी हैं, और सेना अमेरिका के सुर में बात करती दिख रही है। नतीजा यह है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई है। श्रीलंका की स्थिति बेहद विपरीत है, जहां उसके पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है और बत्ती गुल है। महिंदा राजपक्षे की सरकार गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। कहा जा रहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के लिए उन्होंने चीन से ऊंची ब्याज दर पर जो लोन लिए थे, इसकारण देश की कमर टूट गई है। फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, ताकि लोगों को आंदोलन करने से रोका जा सके ।

दिवंगत पिता के नाम आवंटित बंगले से निकाले जाने पर बोले चिराग पासवान

नई दिल्ली ।

अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को राष्ट्रीय राजधानी में आवंटित बंगला '12 जनपथ से बेदखल किये गये जाने के बाद लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जो चीज सरकारी है, उसके साथ किसी तरीके का मोह रखना गलत है। मुझे मेरा सौभाग्य था कि मुझे इतने समय तक उस घर में रहने का अवसर मिला। उस घर में मेरे पिताजी ने न सिर्फ राजनीतिक जीवन की एक लंबी पारी खेली, बल्कि सामाजिक न्याय की वह जन्म भूमि रही है। उसी घर में पापा ने पार्टी बनाई थी। उसी घर में ऊंची जाति के जो गरीब थे, उनको आरक्षण देने की सोच रखी गई थी। जब लॉकडाउन लगा था और पापा उस घर में तस्वीरें देखते थे कि मजदूर जा रहे हैं, उनको इस बात की चिंता सताती थी कि वह खाना कैसे खाएंगे। चिराग ने कहा कि घर का मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल ये घर मुझे खाली करना ही था। जो घर खाली करवाने का तरीका था, मुझे उस तरीके से दिक्कत है। घर खाली करवाते समय मेरे पिताजी की तस्वीरों को फेंका गया। घर के कोने-कोने में जिन महापुरुषों की तस्वीरें लगी थीं, उन्हें जिस तरीके से सड़क पर फेंका गया, मुझे उससे दिक्कत है। मेरे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि मैं 29 तारीख की रात में घर को खाली करने के लिए तैयार था। मुझे नहीं पता, क्यों मुझे बुला के वादा किया गया? क्यों केंद्रीय मंत्री के फोन आए? क्यों मुझे रोका गया? यह अलग राजनीतिक चर्चा का विषय है।

दिवंगत अहमद के सुपुत्र फैसल ने टवीट ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता, इंतजार करके थक गया हूं

नई दिल्ली ।

गुजरात से आने वाले अहमद पटेल को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का करीबी और कांग्रेस का संकटमोचक समझा जाता था। लेकिन अब अहमद पटेल के निधन के बाद उनके बेटे फैसल पटेल ही कांग्रेस का संकट बढ़ाते दिख रहे हैं। इसका संकेत उन्होंने ट्वीट कर दिया है। फैसल ने ट्वीट कर लिखा, इंतजार करके थक गया हूं। हाईकमान से प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने विकल्पों को खुला रखकर चल रहा हूं। उनके ट्वीट को फैसल पटेल के अगले राजनीतिक कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां कहा जाने लगा है, कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस छोड़कर किसी और दल का हाथ थाम सकते हैं। फैसल के पिता अहमद पटेल दशकों तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा रहे और सोनिया गांधी के करीबी थे। नवंबर 2020 में अहमद का कोरोना के चलते निधन हो गया था। फैसल ने अपने ट्वीट में इसका कोई जिक्र नहीं किया है, कि वह हाईकमान से किस तरह के प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि उनके राजनीतिक बैकग्राउंड को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह राजनीति में पदार्पण कर सकते हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस की बजाय किसी और राजनीतिक दल के जरिए वह ऐसा कर सकते हैं। प्रोत्साहन न मिलने वाली बातको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वह गुजरात में अहम भूमिका की उम्मीद कांग्रेस से कर रहे थे, जो उन्हें नहीं मिल सकी। प्रोत्साहन न मिलने वाली बातको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वह गुजरात में अहम भूमिका की उम्मीद कांग्रेस से कर रहे थे, जो उन्हें नहीं मिल सकी। इससे पहले फैसल पटेल ने इसका संकेत दिया था कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भरूच से चुनाव लड़ सकते हैं। पिता के निधन के बाद फैसल पटेल ने कहा था कि मेरी रुचि इस बात में है कि कैसे अहमद पटेल की ओर से शुरू किए सामाजिक कार्यों को वह आगे बढ़ा सकें। पटेल परिवार के दो अस्पताल हैं और एक स्कूल भी है, जिसे वे संचालित करते हैं। फैसल ने कहा था, यदि हाईकमान चाहेगा, तब फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरी पसंद भरूच इलाका होगा, जो मेरा इलाका रहा है।% गौरतलब है कि फैसल पटेल की मुलाकात आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से भी हो चुकी है। उस मीटिंग की काफी चर्चा हुई थी। इसके बाद फैसल के ट्वीट के चलते इस बात के कयास भी लग रहे हैं कि वह भविष्य में आम आदमी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं।

कोवैक्सीन के संबंध में डब्ल्यूएचओं की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगाः भारत बायोटेक

हैदराबाद । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा संयुक्त राष्ट्र की खरीद एजेंसियों के माध्यम से कोवैक्सीन की आपूर्ति निलंबित करने की घोषणा के बीच भारत बायोटेक के सूत्रों ने कहा कि दवा कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी को कोविड-19 टीके की आपूर्ति नहीं की है और निलंबन का कोई असर महसूस नहीं होगा। दवा कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अब तक कंपनी ने केंद्र सरकार के 'टीका मैत्री कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार और नौ देशों को टीकों की आपूर्ति की है, और आपातकालीन उपयोग मंजूरी (ईयूए) के तहत प्रत्यक्ष वाणिज्यिक आपूर्ति की है। कोवैक्सीन को 25 से अधिक देशों से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। कंपनी के सूत्र ने कहा, ''भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए लाइसेंस मिलने के बाद, हमने डब्ल्यूएचओ के साथ आपातकालीन उपयोग के वास्ते सूचीबद्ध (ईयूएल) किए जाने के लिए आवेदन किया और हमें वह भी मिल गया। ईयूएल का इरादा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और गावी कोवैक्स सुविधा जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को टीकों की आपूर्ति करना था। सूत्र ने कहा, ''लेकिन हमें आज तक संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी से कोई'ऑर्डर' नहीं मिला है। इसकारण हमने अभी तक कोई आपूर्ति नहीं की है। हमने केवल भारत सरकार और कुछ अन्य देशों को टीकों की आपूर्ति की है, लेकिन ये सभी आपूर्ति उन देशों से प्राप्त ईयूए पर आधारित थी।'' अंतरराष्ट्रीय टीका गठबंधन 'गावी कोवैक्स' ने भी कोवैक्सीन के लिए कोई 'ऑर्डर' नहीं दिया है। डब्ल्यूएचओ ने अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) में कमियों का हवाला देकर दो अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र की खरीद एजेंसियों के माध्यम से कोवैक्सीन की आपूर्ति को स्थगित करने की पुष्टि की थी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)

क्रांति समय
Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्राइम ब्रांच में महिला के रूप में पहले डीसीपी का पदभार संभाला

क्रांति समय,सूरत
www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

सूरत के इतिहास में पहली बार रूपल सोलंकी को अपराध शाखा में महिला डीसीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। सूरत क्राइम ब्रांच के डीसीपी का पदभार संभालते हुए 14 फरवरी को मां बनी रूपल सोलंकी ने कहा कि एक महिला मां बनने पर मजबूत होती है। टीम शहर में अपराध दर को कम करने के लिए मिलकर काम करेगी। साथ ही टीम में अधिक रुचि लेकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यभार संभालने के लिए तैयार सूरत में पहली बार महिता डीसीपी का पदभार संभाल रहे रूपल सोलंकी ने कहा कि पुलिस विभाग में पुरुष-महिला जैसा कोई भेदभाव नहीं है. मैंने पुलिस विभाग में ऐसा भेदभाव कभी महसूस नहीं किया। इसके साथ जो जिम्मेदारी आती है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना होता है. सूरत में पहली बार मुझे इस तरह की जिम्मेदारी मिली है जिसे पूरा करने के लिए मैं उत्साहित हूं।

14 फरवरी को परिवार में दूसरे बच्चे के रूप में एक बेटे को जन्म देने वाली रूपल सोलंकी ने कहा, ''मैंने मैरी कॉम नाम की एक फिल्म देखी ।'' जिसमें मैरी कॉम अपने जुड़वा बच्चों के साथ ट्रेनिंग करने कोच के पास जाती हैं। मुझे याद है इस फिल्म का एक डायलॉग यह है कि एक महिला मां बनने पर मजबूत होती है। मैं अपने काम के साथ-साथ परिवार का भी ख्याल रखूंगा।

महिलाओं के लिए भी काम करूंगा सूरत में अपराध दर को कम करने के लिए सरकार के साथ और आयुक्त के मार्गदर्शन में काम करने के लिए, रूपल सोलंकी ने कहा, शहर में महिलाओं के लिए कौन सी टीम काम कर रही है। मैं इस टीम में भी दिलचस्प तरीके से काम करूंगा। उन्होंने कहा कि साथ ही बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या को कम करने के प्रयास किए जाएंगे।

केजरीवाल रोड शो कर दिल्ली पहुंचे और गुजरात आप के नेता भाजपा में शामिल हो गए

क्रांति समय,सूरत
www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

गुजरात विधानसभा के इस वर्ष होनेवाले चुनावों को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन सबके के बीच दलबदल का भी दौर शुरू हो गया है। गत शनिवार को आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दो दिवसीय गुजरात दौरे पर आए थे। गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल और मान ने पूर्वी अहमदाबाद में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया था। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली और भगवंत मान के पंजाब लौटते ही गुजरात आप के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भगवा धारण कर लिया। जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल उधर दिल्ली पहुंचे और इधर गुजरात आप के 150 जितने नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। गुजरात भाजपा के महासचिव प्रदीपसिंह वाघेला के मुताबिक दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अपने घर पहुंचे ही होंगे कि इधर गुजरात आप के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा जॉइन कर ली। आप नेता और कार्यकर्ताओं के हृदय परिवर्तन से स्पष्ट हो गया कि गुजरात की जनता को कोई ठग नहीं सकता। गुजरात की जनता का आशीर्वाद भाजपा के लिए है और यही वजह है कि आप के नेता व कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ रहे हैं।

वैश्विक शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में विश्व बैंक का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गुजरात दौरे पर

क्रांति समय,सूरत
www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

विश्व बैंक का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गुजरात में विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में हो रहे आमूल परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए आज हमारे राज्य के दौरे पर आया है। वॉशिंगटन स्थित विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक हैमे सावेद्रा के नेतृत्व में यह प्रतिनिधमंडल गुजरात की यात्रा पर आया है। हैमे सावेद्रा दक्षिण अमेरिकी देश पेरूके शिक्षा मंत्री रह चुके हैं तथा वर्तमान में विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक हैं। सावेद्रा गुजरात में विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 'मिशन स्कूल्स ऑफ़ एक्सीलेंस' के माध्यम से हो रहे आमूल परिवर्तनों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (सीसीसी) के माध्यम से हो रहे डेटा आधारित इनिशिएटिव्स से प्रभावित हुए हैं। इसीलिए हैमे सावेद्रा सीसीली एवं शैक्षिक सुधारों के गुजरात मॉडल का स्व-अध्ययन कर उसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस घोषित करने के लिए आज गुजरात आए हैं। इस अवसर पर श्री हैमे सावेद्रा ने कहा कि यह हमारे लिए ख़ुशी की बात है कि हमें गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे उत्कृष्ट कार्य देखने का अवसर मिला। समग्र विश्व की तुलना में गुजरात में शिक्षा का योगदान सही दिशा में जा रहा है। गुजरात विद्यार्थियों को सुविधाएँ उपलब्ध करा रहा है, वह प्रशंसनीय है। सरकार के प्रयासों से विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी प्रशंसनीय है कि गुजरात ने स्कूलिंग के साथ-साथ लर्निंग पर भी विशेष बल दिया है। गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के फ़ोकस तथा माइंड सेट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें शिक्षकों तथा आचार्यों का भी यह प्रयास होता है कि विद्यार्थी कुछ नया सीखें। उन्होंने कहा कि कई बार हमें लगता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो पढ़ाई ही करते होंगे, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसलिए प्रोडक्टिव लाइफ़ के लिए स्कूल में शिक्षा के साथ-साथ फ़ंडामेंडल स्किल्स भी होना ज़रूरी है। राज्य सरकार गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में सदैव नए-नए शैक्षिक सुधार लागू कर शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए कटिबद्ध है। स्कूलिंग सुनिश्चित करने के बाद प्रत्येक बच्चे की लर्निंग भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा गुणवत्ता सुधार के श्रृंखलाबद्ध क़दम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ढाँचागत रूप से श्रेष्ठ बनाया जाए और बच्चों को शिक्षा सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम्स, स्टेम लैब, सह-आभ्यासिक प्रवृत्तियों से युक्त आकर्षक स्कूल उपलब्ध हों, तो शिक्षा गुणवत्ता में अधिकतम् सुधार हो सकते हैं। उत्तम तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में आगामी पाँच वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 'मिशन स्कूल्स ऑफ़ एक्सीलेंस' चलाने का निश्चय किया गया है। स्कूल्स ऑफ़ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के माध्यम से आगामी पाँच वर्षों में सभी 35,122 सरकारी विद्यालयों तथा 5,847 ग्रांट-इन-एड विद्यालयों सहित कुल लगभग 41,000 सरकारी व ग्रांट-इन-एड विद्यालयों को 'मिशन स्कूल्स ऑफ़ एक्सीलेंस' के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इन विद्यालयों में से 20,000 विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने के लिए विश्व स्तरीय ढाँचागत सुविधाएँ तथा शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इन स्कूलों में आगामी पाँच वर्षों में कुल 50,000 नए क्लासरूम्स का निर्माण, 1,50,000 क्लासरूम्स में स्मार्ट क्लास की सविधा, 20,000 नए कम्प्यूटर लैब, 5,000 स्टेम लैब / टिंकरिंग लैब आदि मुहैया कराने का लक्ष्य है, जिसके माध्यम से अगले पाँच वर्षों में राज्य के लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों को सीधा लाभ होगा। राज्य के अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों वर्ल्ड बैंक (डब्ल्यूबी) तथा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) द्वारा 1 (एक) बिलियन यूएस डॉलर यानि लगभग 7,500 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। विश्व बैंक की ओर से शिक्षा क्षेत्र में समग्र भारत में अब तक की सबसे बड़ी फ़ंडिंग 'मिशन स्कूल्स ऑफ़ एक्सीलेंस' के लिए की गई है तथा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) समग्र विश्व में शिक्षा क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर गुजरात के शिक्षा भाग के साथ कार्य कर रहा है। समग्र देश में स्कूली शिक्षा को गुणवत्तायुक्त बनाने का इस प्रकार का यह पहला प्रोजेक्ट है। आगामी 5 से 6 वर्षों की समयावधि में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के लगभग एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा और यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी, शिक्षा राज्य मंत्री कुबेर डिंडोर, विश्व बैंक के भारत स्थित प्रतिनिधि डॉ. शबनम सिन्हा, राज्य के शिक्षा सचिव डॉ. विनोद राव, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य निदेशक रतनकँवर गढवी सहित अधिकारी उपस्थित थे।